Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 74
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.0
रविवार, 22 मार्च, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 चवदार तालाब सत्याग्रह से समानता का ...
4 सवालों के घेरे में नीतीश कुमार की विदाई...
7 आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी....

संक्षिप्त न्यूज

पश्चिम एशिया में संघर्ष से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर; कपिल सिब्बल ने जताई गंभीर चिंता

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है, खासकर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के मद्देनजर। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के होर्मुज जलडमरूमध्य से आता है। सिब्बल के अनुसार, ईरान जैसे देशों द्वारा खाड़ी क्षेत्र में पेट्रोलियम और गैस संसाधनों पर की जाने वाली जवाबी कार्रवाई भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है, क्योंकि हम वहां से आने वाली गैस, एलपीजी और कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर चुप्पी न साधने और सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया है।

भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। कई रिपोर्टों के अनुसार, देश अपनी कुल कच्चा तेल आवश्यकता का लगभग 85इ आयात करता है, और यह आयात होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील मार्गों से होता है। यह निर्भरता भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है।

पश्चिम एशिया संघर्ष का प्रभाव

पश्चिम एशिया में जारी युद्धों का सीधा असर भारत के गैस पर निर्भर उद्योगों और बंदरगाह आधारित व्यापार पर भी पड़ रहा है। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ और महासचिव रंजीत मेहता ने चिंता व्यक्त की है कि यह युद्ध भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है, जिससे बंदरगाहों पर अफरा-तफरी का माहौल है और गैस आपूर्ति पर निर्भर व्यवसायों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत, पश्चिम एशिया में शांति पर जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियन से फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन को ईद और नवरोज़ की शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि ये पर्व पूरे क्षेत्र में शांति और विकास का संदेश लेकर आएंगे।

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित

करती हैं।

प्रधानमंत्री ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को भी दोहराया। साथ ही, ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान सरकार के सहयोग की सराहना की।

बताया गया है कि हालिया तनाव की स्थिति के बाद यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को लेकर सरकार ने स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उपयोग युद्धविराम के लिए करना चाहिए था।

इस प्रकार, जहां एक ओर सरकार कूटनीतिक स्तर पर शांति और स्थिरता की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है।

नवरात्रि का चौथा दिन

मां कूष्मांडा

नवरात्रि के चौथे मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी. कहते हैं जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था, तब मां कूष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी. इन्हें सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाता है. मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने वालों को रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है. कहते हैं मां कूष्मांडा जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे अष्ट सिद्धियां और निधियां प्राप्त हो जाती है.

मां कूष्मांडा की पूजा विधि

नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान आदि के बाद हरे रंग के वस्त्र पहने. इस दिन कुम्हड़े की बलि देकर माता को अर्पित करना चाहिए. कुम्हड़ा वो फल है जिससे पेठा बनता है. माता को मेहंदी, चंदन, हरी चूड़ी, चढ़ाएं. देवी कूष्मांडा का प्रिय भोग मालपुआ है. लंबे वक्त से अगर कोई घर में बीमार है या आए दिन बीमारियों का डेरा रहता है तो माता कूष्मांडा के बीज मंत्र का 108 बार जाप या देवी कवच का पाठ करें. माता की कथा सुनें. मान्यता है इससे असाध्य रोग भी खत्म हो जाते हैं.

मां कूष्मांडा का प्रिय भोग - मालपुआ
मां कूष्मांडा का प्रिय रंग - हरा

मां कूष्मांडा के उपाय

जानकारों के अनुसार देवी के इस स्वरूप की उपासना से कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर किए जा सकते हैं. मां कूष्मांडा की पूजा वाले दिन बुध के अशुभ प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति के उम्र जितनी हरि इलाइची लें और फिर एक-एक कर ये इलाइची मां के चरणों में चढ़ाते जाएं. इस दौरान ये मंत्र बोलें 'ॐ बुं बुधाय नमः'. अगले दिन सारी इलाइची को एकत्र करके हरे कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख लें. मान्यता है इससे वाणी और बुद्धि में निखार आता है और स्वास्थ लाभ मिलता है.

मां कूष्मांडा मंत्र

कुष्मांडाः ऐं ह्री देव्यै नमः
वन्दे वांछित कामर्थे चन्द्रार्घकृत शेखराम्। सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्माण्डा यशस्वनीम्
ॐ कूष्माण्डायै नमः
सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च। दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे।

तमिलनाडु चुनावः

अमित शाह से मिले एएमएमके प्रमुख दिनाकरन, डीएमके को हराने के लिए रणनीति पर हुई चर्चा

नई दिल्ली/चेन्नई। तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) पार्टी के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने शनिवार को जानकारी दी कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को हराने की रणनीति पर चर्चा की।

सीट बंटवारे पर दिनाकरन ने क्या कहा?

टीटीवी दिनाकरन ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ के साथ बैठक में सीट-बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने (अमित शाह) यह बात की कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक दल 234 विधानसभा क्षेत्रों में एकजुट होकर काम करें। चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करें।'

दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई?

पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिनाकरन ने कहा, उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं और सलाह दी है। मैं इसी मकसद से यहां (नई दिल्ली) आया था। दिनाकरन ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से

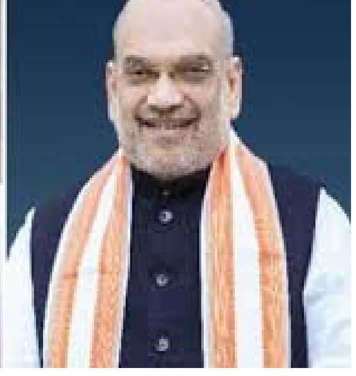

मुख्य रूप से यही चर्चा करने के लिए मुलाकात की और सीट बंटवारा अगले दो-तीन दिनों में सौहार्दपूर्ण तरीके से चेन्नई में तय किया जाएगा। एएमएमके प्रमुख ने कहा, हम भ्रष्ट डीएमके सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। लोग हमारे साथ हैं। हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे और तमिलनाडु में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनाएंगे।

बार-बार दिल्ली आने के सवाल पर क्या कहा? दिनाकरन से जब मीडिया ने पूछा, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यह आलोचना की थी कि पल्लानीस्वामी बार-बार दिल्ली जाते हैं और भाजपा नेताओं से बातचीत करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव तमिलनाडु की स्थानीय टीम और दिल्ली की टीम के बीच की लड़ाई बन गया है। इस पर टीटीवी धनकरन ने सवाल किया, क्यों, क्या आपको हमारे दिल्ली आने से कोई दिक्कत है?

उन्होंने कहा, डीएमके क्या कहता है,आप वही क्यों दोहराना चाहते हैं। हमें पता है कि उन्होंने पहले दिल्ली में क्या किया। स्टालिन चुनाव में हार के डर से यह बात कर रहे हैं कि यह तमिलनाडु टीम बनाम दिल्ली टीम है। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स में कई गैर-तमिल खिलाड़ी हैं, जिनमें कप्तान भी शामिल है। मुख्यमंत्री इसका क्यों विरोध नहीं करते?

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का मुंबई आगमन

मुंबई। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर दोपहर 1:10 बजे आगमन हुआ।

राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन

भारती तथा सचिव एवं मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांडे उपस्थित रहे।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने-सामने

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय तेज़ उबाल पर है और चुनावी मुकाबला अब केवल वोटों की लड़ाई न रहकर पहचान, प्रतीकों और भावनाओं की टक्कर बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच यह संघर्ष अब और अधिक तीखा हो गया है।

ईद के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नमाज में शामिल हुईं और लोगों को बधाई देते हुए अल्लाह के आशीर्वाद की बात की। उनके इस कदम को राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपना संदेश मजबूत करने की कोशिश की। अपने संबोधन में उन्होंने मतदाता अधिकारों और चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए, जिससे उन्होंने खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों की पक्षधर के रूप में प्रस्तुत किया।

दूसरी ओर, भाजपा नेता शुभेंदु

अधिकारी ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां काली का आशीर्वाद लिया और सनातन परंपरा के समर्थन का संदेश दिया। इसे भाजपा की ओर से बहुसंख्यक सांस्कृतिक पहचान को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

दोनों नेताओं की ये गतिविधियां अपने-अपने मतदाताओं के लिए स्पष्ट राजनीतिक संकेत मानी जा रही हैं। एक ओर अल्पसंख्यक वर्ग को साधने का प्रयास दिख रहा है, तो दूसरी ओर बहुसंख्यक पहचान को मजबूत करने की कोशिश।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की राजनीति से राज्य में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का आगामी चुनाव केवल विकास और योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह विचारों, पहचान और प्रभाव की एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन चुका है।

ईरान पर हमले को 21 दिन, मोदी सरकार पर कांग्रेस का सवाल–जयराम रमेश का तीखा हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईरान पर अमेरिका और इज़रायल द्वारा किए गए हमलों को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे 'नैतिक कायरता' और भारत के सभ्यतागत मूल्यों के साथ 'राजनीतिक विश्वासघात' बताया।

जयराम रमेश ने कहा कि ईरान पर हवाई हमले शुरू हुए तीन सप्ताह (21 दिन) से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मोदी सरकार ने न तो इन हमलों की निंदा की है और न ही तनाव कम करने के लिए कोई ठोस कूटनीतिक पहल की है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने अमेरिका और इज़रायल द्वारा किए गए हमलों, लक्षित हत्याओं और ईरान में सत्ता परिवर्तन के प्रयासों की आलोचना की है? उनके अनुसार, इन सभी सवालों का जवाब 'नहीं' है।

रमेश ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव और संभावित आर्थिक संकट को लेकर कोई सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उपयोग कर युद्धविराम के प्रयास करने चाहिए थे।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की यह निष्क्रियता भारत की वैश्विक भूमिका और उसके पारंपरिक मूल्यों के विपरीत है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिससे भारत सहित कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

पूर्व सीएम पटनायक ने छह विधायकों को निलंबित किया; राज्यसभा चुनावों में हुई थी क्रॉस-वोटिंग

भुवनेश्वर / नई दिल्ली। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने हालिया राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छह विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है।

बीजद की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक में इन विधायकों के निलंबन का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। इन छह विधायकों को 17 मार्च को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। उन्होंने शुक्रवार शाम तक अपने जवाब भेजे। लेकिन, बीजद की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक ने कहा कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए।

हाल ही में हुए द्विवार्षिक चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चार में से दो राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल की। जबकि, विपक्षी बीजद और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को एक-एक सीट मिली। ओड़िशा विधानसभा में कुल 147 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थक विधायकों और निर्दलीय विधायकों की संख्या 82 थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को पहली पसंद के रूप में कुल 93 मत मिले, जो उनकी वास्तविक संख्या से 11 अधिक थे। इन 11 अतिरिक्त मतों में आठ वोट बीजू जनता दल के विधायकों और तीन वोट कांग्रेस के विधायकों के थे।

'कागज पर नहीं, वास्तविक अनुभवों में दिखे समानता', महिला वकीलों के सर्वेक्षण पर बोले सीजेआई

बंगलूरू। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशे में महिलाओं के लिए औपचारिक समानता को वास्तविक अनुभवों में बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, महिलाओं की निरंतर भागीदारी और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधार और संस्थागत समर्थन जरूरी हैं।

बंगलूरू के बाहरी इलाके में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय सम्मेलन-2026 आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का विषय 'न्यायिक शासन की पुनर्कल्पना-लोकतांत्रिक न्याय के लिए संस्थाओं को मजबूत करना' रखा गया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेआई ने महिला वकीलों की ओर से किए गए सर्वेक्षण के नतीजों को साझा किया। उन्होंने कहा, यह सर्वेक्षण दिखाता है कि महिलाओं को कानूनी पेशे में आने वाली दिक्कतों और उनके समाधान के लिए प्रणालीगत उपायों की जरूरत है।

महिला वकीलों के सर्वेक्षण को सराहा सीजेआई ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जब हम हमारे सांविधानिक ढांचे में समानता की बात करते हैं, तो

यह केवल कागज पर नहीं होना चाहिए। इसलिए समानता को वास्तविक अनुभवों में बदलना जरूरी है। उन्होंने महिला वकीलों की ओर से किए गए सर्वेक्षण की सराहना की और इसे बहुत ही उल्लेखनीय व वैज्ञानिक सर्वेक्षण बताया।

उन्होंने कहा, यह आंखें खोल देने वाला है और चुनौतियों व समाधानों को पहचाने के लिए रोडमैप भी प्रदान करता है।

ये भी पढ़ेंः पूर्व सीएम पटनायक ने बीजद के छह विधायकों को निलंबित किया; राज्यसभा चुनावों में हुई थी क्रॉस-वोटिंग

निरंतर प्रयासों से कम होगा लिंग आधारित भेदभावः सीजेआई

उन्होंने आगे कहा, यह रिपोर्ट (सर्वेक्षण) हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। हमें इसे छोटे संविधान के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि निरंतर प्रयासों से लिंग आधारित भेदभाव कम किया जा सकता है और सांविधानिक समानता का वादा पूरा किया जा सकता है सीजेआई ने इस बात पर खुशी भी जताई कि अब कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों में पचास फीसदी से अधिक महिलाएं हैं। कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाले नए वकीलों में भी महिलाओं की अहम भागीदारी है।

सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

गंगटोक। सिक्किम के गंगटोक और पाक्योंग जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एडवाइजरी में क्या कहा गया?

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, अगले 24 घंटों में 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन होने की संभावना है। एडवाइजरी में कहा गया कि क्षेत्र में बदलते मौसम के कारण बर्फ अस्थिर हो सकती है, जिससे हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

शुक्रवार सुबह से हो रही भारी बारिश अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों को आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, हिमालयी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। इस बीच, भारी बर्फबारी के कारण गंगटोक से सोमगो झील और नाथुला जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है।

शराब के नशे में चूर पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई के वडाला इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शराब को लेकर हुए विवाद में एक 29 वर्षीय महिला की उसके पति ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतका की पहचान कविता महेश वड के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी पति महेश नारायण वड फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच में सामने आया है कि आरोपी महेश ने पत्नी कविता को लात-घूंसे से बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई काले-नीले निशान पाए गए हैं, जो गंभीर मारपीट की पुष्टि करते हैं.

BNS की धारा 103 के तहत मामला दर्ज

वडाला पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया

गया है. शिकायत मृतका के भाई शुभम रमेश लोदी ने दर्ज कराई है, जो नवी मुंबई के नेरुल के निवासी हैं और मूल रूप से रायगढ़ जिले के मुरुद के रहने वाले हैं.

पति-पत्नी के बीच अक्सर होते थे झगड़े

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि महेश शराब का आदी था और इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे. घटना के दिन भी महेश नशे की हालत में घर पहुंचा, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई. गुस्से में आकर उसने कविता पर हमला कर दिया और मोबाइल फोन भी उसके चेहरे पर फेंका, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गंभीर हालत के बावजूद आरोपी ने कविता को तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिससे उसकी स्थिति और बिगड़ गई. बाद में जब वह बेहोश हो गई, तब उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दो टीमें बनाई थीं. आखिरकार आरोपी को उसके एक रिश्तेदार के घर से दबोच लिया गया. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

संजय राउत की संयुक्त राष्ट्र से अपील, चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल

दिव्यांश

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने भारत की चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह अपने प्रतिनिधियों को भारत भेजकर चुनावों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करे।

पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर भारत के लोकतंत्र की सराहना करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में चुनावों के दौरान हेरफेर, दबाव, धनबल और मतदाता सूची में गड़बड़ी जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं।

राउत ने दावा किया कि जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्र की सत्ता में आए हैं, तब से ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक कोई भी चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि पहले बूथ कब्जाने जैसी घटनाएं होती थीं, लेकिन अब नए तरीकों से चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं।

उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह संस्था अब स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है। राउत ने पश्चिम बंगाल की स्थिति का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि

वहां अघोषित रूप से राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति है और इसे उन्होंने 'अघोषित आपातकाल' तक बताया।

संजय राउत ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार होती, तो वहां हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में विभिन्न राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ है, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।

सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी 20 जून को तय

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार की नातिन और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले जल्द ही विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, रेवती सुले का विवाह नागपुर के उद्योगपति सारंग अरुण लखानी के साथ 20 जून को मुंबई में संपन्न होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विवाह समारोह मुंबई के एक प्रतिष्ठित स्थान पर भव्य और शाही अंदाज में आयोजित किया जाएगा। पवार और लखानी परिवार इस आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। समारोह में महाराष्ट्र तथा देश के कई प्रमुख राजनीतिक नेता, उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।

विवाह के बाद स्वागत समारोह भी भव्य रूप से आयोजित किए जाएंगे। पहला स्वागत समारोह मुंबई में होगा। चूंकि दूल्हा नागपुर से है, इसलिए वहां भी एक विशेष स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर पवार परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए दिल्ली में भी एक भव्य स्वागत समारोह होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, इस विवाह का संबंध

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मध्यस्थता से तय हुआ था।

सारंग लखानी के बारे में

सारंग अरुण लखानी, उद्योगपति अरुण लखानी के पुत्र हैं, जो विश्वराज समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। सारंग लखानी एक कुशल बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।

रेवती सुले के बारे में

रेवती सुले, सुप्रिया सुले और सदानंद सुले की पुत्री हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। रेवती ने बारामती लोकसभा चुनाव में अपनी माता सुप्रिया सुले के प्रचार अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

बीएमसी मेयर के सरकारी बंगले का होगा कायाकल्प, 1.5 करोड़ रुपये की लागत से चल रहा है नवीनीकरण कार्य

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बीएमसी मेयर रितु तावड़े के सरकारी आवास का अब कायाकल्प होने जा रहा है. भाईखला में स्थित यह ऐतिहासिक बंगला करीब 6,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां बड़े स्तर पर नवीनीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है. लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट में भवन की संरचनात्मक मरम्मत, दीवारों की रंग-रोगन, लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिशिंग और छत को मजबूत करने जैसे अहम काम शामिल हैं.

लंबे समय से मरम्मत की जरूरत महसूस कर रहे इस बंगले को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित और आकर्षक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. ताकि यह विरासत और उपयोगिता दोनों में संतुलन बना सके.

मेयर के बंगले का शुरू हुआ नवीनीकरण

जानकारी के अनुसार, नवीनीकरण की योजना में इटैलियन मार्बल की फ्लोरिंग, नए झूमर, आधुनिक लाइट फिक्स्चर और वेनेशियन ब्लाइंड्स लगाना शामिल है. साथ ही, बंगले के सभी फर्नीचर को पूरी तरह से बदला जाएगा. भूतल (ग्राउंड फ्लोर) के लेआउट को इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा कि वहां एक नया 'लिविंग स्पेस' बन सके, जबकि

मौजूदा कॉन्फ्रेंस रूम को बदलकर 'गेस्ट एरिया' बनाया जाएगा.

1.5 करोड़ रुपये की लागत से होंगे सभी कार्य

नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, इन कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है. चूंकि 2022 में प्रशासक का कार्यकाल शुरू होने के बाद से यह बंगला खाली पड़ा था, इसलिए इसकी हालत काफी खराब हो गई थी. नतीजतन, आगामी चुनावों को देखते हुए, बंगले की मरम्मत और नवीनीकरण के काम में तेजी लाई गई है.

अभी अपने निजी आवास में रह रही हैं मेयर

इस बीच, मेयर रितु तावड़े फिलहाल घाटकोपर स्थित अपने निजी आवास में रह रही हैं. यह स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने इन नवीनीकरण कार्यों के संबंध में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया था. इसके अलावा, यह भी कहा गया कि मेयर का आवास नगर निगम की संपत्ति है और इससे संबंधित सभी निर्णय निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही लिए जा रहे हैं.

अशोक खरात मामले में बड़ी खबर, महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने दिया इस्तीफा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

एनसीपी अजीत पवार गुट की नेता और महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. नासिक के फर्जी बाबा अशोक खरात कांड उजागर होने और बाबा के साथ नजदीकियों का खुलासा होने के बाद लगातार रुपाली के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. खरात की कई नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं. खरात के पास के कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं. सीएम देवेंद्र फडणवीस को भेजे गए इस्तीफे में रुपाली चाकणकर ने कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रही हैं.

15 अक्टूबर 2024 को पद पर हुई थी नियुक्ति

अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा, '15 अक्टूबर 2024 को मेरी नियुक्ति महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में हुई थी. व्यक्तिगत कारणों के चलते मैं स्वेच्छा से उक्त पद से अपना इस्तीफा इस पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूं. अब तक आपने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया और मुझे जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं आपकी एवं सभी सहयोगियों की हृदय से आभारी हूं. भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है. अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत अध्यक्षा,

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग पद से इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें.'

कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा?

अशोक खरात को 'कैप्टन' खरात के नाम से भी जाना जाता है. उसे 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोन्धे ने कहा कि खरात मामले की एसआईटी जांच का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रैंक की महिला पुलिस अधिकारी को करना चाहिए.

'खरात की बातों में आकर रुपाली ने काटी अपनी उंगली'

वहीं उद्धव गुट की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए चाकणकर का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि रुपाली चाकणकर ने खरात की बातों में आकर अपनी उंगली काट ली थी. अंधारे ने ऐसी तस्वीरें भी दिखाईं जिनमें चाकणकर की अनामिका उंगली पर पट्टी बंधी हुई दिख रही है.

18 मार्च को गिरफ्तार हुआ फर्जी बाबा अशोक खरात को बुधवार (18 मार्च) को नासिक जिले में एक महिला का तीन साल तक बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने दावा किया कि आरोपी ने विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं का शोषण किया. उपायों और सलाह के माध्यम से धनवान भक्तों से पैसे वसूले. एनसीपी के सीनियर नेता प्रफुल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि खरात प्रकरण में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अशोक खरात की तुलना अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी रहे जेफरी एपस्टीन से की. उन्होंने कहा कि जिस तरह एपस्टीन मासूम बच्चियों का शोषण करता था, वैसे ही खरात पर भी गंभीर आरोप लगे हैं. उन्होंने इस मामले को 'खरात फाइल्स' करार दिया.

ठाणे में क्रूरता की घटनाः बंदर के आर-पार हुआ तीर, वन विभाग ने शुरू की जांच

ठाणे। मुंबई से सटे ठाणे में अमानवीयता की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के पास एक बंदर को धनुष-बाण से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

सूचना मिलते ही रेस्क्यू संस्था और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिक द्वारा हेल्पलाइन पर सूचना दी गई थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि बंदर पेड़ पर बैठा था और उसके श्रोणि (पेल्विक) हिस्से में तीर आर-पार घुसा हुआ था। यह दृश्य देखकर रेस्क्यू टीम भी हैरान रह गई और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया।

गंभीर हालत, सर्जरी की जरूरत

घायल बंदर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पशु चिकित्सक डॉ. प्रीति साठे की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार बंदर की हालत गंभीर है और उसे बचाने के लिए बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के बाद उसे 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा।

वन विभाग की सख्त कार्रवाई की तैयारी

वन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि इस्तेमाल किया गया तीर पेशेवर आर्चरी में उपयोग होने वाला हो सकता है।

मध्य रेल

भुसावल मंडल

खुली ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए, मंडल रेल प्रबंधक (सिग्नल एवं दूरसंचार) मध्य रेल, भुसावल द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरीत ऑन लाइन खुली ई–निविदाऐं पात्र निविदाकर्ताओं से निम्न लिखित कार्य के लिए आमंत्रित की जाती है। **ई–निविदा सूचना सं.** बीएसएल-एन-एसएंडटी - 41-2025-26 दिनांक 18.03.2026 **कार्य का नाम**–ट्रैक के साथ सुरक्षा फेंसिंग के संबंध में सिग्नलींग कार्य तथा IGP-BSL, एवं MMR-ANK सेक्शन में 09 सबवे के प्रावधान हेतु कार्य, भुसावल डिविजन में **कार्य की अनुमानित लागत**– ₹. 2,98,96,892.29(रूपये दो करोड अठ्ठानवे लाख छियानवे हजार आठ सौ बानवे रूपये उन्नतीस पैसे मात्र)। **निविदा फार्म/बुकलेट की कीमत**–नहीं। **बयाना राशि**– ₹. 5,98,000/– **कार्य पूरा करने का समय**–15 माह एलोए देने के बाद। **निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि**– 30.03.2026। **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय**–13.04.2026 के 15.00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि और समय**– 13.04.2026 के 15.30 बजे (यदि संभव हो तो) **वेबसाइट का विवरण जहां से निविदा सूचना के बारे में पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं :www.ireps.gov.in** **DE/13**

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

ईरान-इजराइल में जारी जंग के बीच शिंदे गुट का बड़ा बयान, 'भारत इसका हिस्सा नहीं है लेकिन...'

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है. इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने युद्ध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है. निश्चित तौर पर भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है क्योंकि पिछले दिनों इजरायल ने ईरान के तेल भंडार, रिफाइनरी पर मिसाइलों से हमला किया. ईरान भी उसी तरीके से जवाब दे रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत इस युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर गंभीरता से काम कर रहा है.

भारत ने इजरायल और ईरान दोनों से

बात की- संजय निरुपम

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, ''भारत की अब तक की जो भूमिका रही है वो बहुत ही अच्छी रही है. भारत ने इजरायल से भी बात की है और ईरान से भी बात की. तमाम अलग-अलग देशों के प्रमुख हैं, खाड़ी देशों के प्रमुख हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं. तमाम अलग-अलग देशों के प्रमुख हैं, खाड़ी देशों के प्रमुख हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं.''

'शांतिपूर्वक कूटनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन हमारी जिम्मेदारी'

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि इस युद्ध में अपने आप को झोंकने और इसमें घी डालकर भड़काने के बजाय शांतिपूर्वक कूटनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है. मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर काम कर रहा है.''

भारत इसमें अहम भूमिका निभाएगा- संजय निरुपम

शिंदे गुट के नेता ने ये भी कहा कि जहां तक हमारी ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरतों का प्रश्न है, उन्हें हल करने के लिए हमारी सरकार ईरान से बात कर रही है और रास्ता भी निकल रहा है ताकि आने वाले दिनों में देश के उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो. उन्होंने कहा, ''ये युद्ध आगे भड़के नहीं, दुनिया को बड़ा नुकसान न हो, निश्चित तौर पर इसमें सबकी भूमिका है और समय आने पर इसमें भारत भी अहम भूमिका निभाएगा.''

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मंडल

विभिन्न इंजीनियरिंग काम

ई-निविदा सूचना संख्या 30 वर्ष 2025-26 दिनांक : 20.03.2026

सं	ई-निविदा संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	EMD राशि
1	DRM-ADI-217-2025-26	आंबली रोड स्टेशन - सहायक मंडल अभियंता - विरमगाम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्लेटफॉर्म की ऊँचाई बढ़ाना, यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराना और अन्य संबंधित कार्य।	14,14,17,225.03	8,57,100.00
2	DRM-ADI-218-2025-26	गांधीधाम – न्यू भुज सेक्शन में वरिष्ठ मंडल अभियंता (NW)-अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में लेवल क्रॉसिंग संख्या 21 कि.मी. 40/9-41/0, 23 कि.मी. 43/3-4, 24 कि.मी. 44/1-2 एवं 26 कि.मी. 45/4-5 को रोड अंडर ब्रिज उपलब्ध कराकर समाप्त करने का कार्य।	43,56,40,137.51	23,28,200.00
3	DRM-ADI-219-2025-26	अहमदाबाद मंडल:- सोनासन, तलोद, राखियाल, आंबलियासन और डाभोडा में कर्मचारियों के लिए पानी की व्यवस्था (OH टैंक, बोरवेल और संप) उपलब्ध कराना (पुनः आमंत्रित)।	1,51,97,859.09	2,26,000.00

ई-निविदा बंद होने की तिथि: दिनांक 15/04/2026 समय 15:00 बजे **कार्यालय का पता:** वरि. मंडल इंजीनियर (सम.)-अहमदाबाद, डी. आर.एम. ऑफिस, चामुंडा ब्रिज के पास, नई स्वदेशी मिल के सामने, नरोडा रोड, अमदुपुरा, अहमदाबाद- 382345 **ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाइट: www.ireps.gov.in**

ADI 312

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

‘डिग्री के साथ कौशल भी जरूरी; उद्यमी बनते समय टाटा का आदर्श अपनाएं’ – उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन

‘विश्वविद्यालयों में नवाचार और प्रयोगशीलता बनी रहनी चाहिए’ – राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आज के समय में केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे रोजगार में बदलना आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक कौशल और बदलती तकनीकों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। उद्यमी बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं को रतन टाटा के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने लाभ के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने यह विचार व्यक्त किए। रत्न टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह लोक भवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, कुलपति डॉ. अपूर्वा पालकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अतिरिक्त

मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, कौशल विकास आयुक्त डॉ. अमित सैनी, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशक डॉ. सतीश सूर्यवंशी तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पहले दीक्षांत समारोह के विद्यार्थी इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। ये छात्र न केवल शैक्षणिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि भारत को ‘वैश्विक कौशल केंद्र’ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव आवश्यक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा और डेटा विश्लेषण जैसे आधुनिक विषयों को शामिल कर छात्रों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए।

उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद वहां की प्रगति का कारण अनुशासन और कड़ी मेहनत है। भारतीय युवाओं को भी इसी समर्पण को अपनाना चाहिए। उन्होंने ‘स्किल इंडिया’ और ‘पीएम-दक्ष’ जैसी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया और कहा कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवनभर सीखते रहने की प्रक्रिया है।

राज्यपाल का संदेशः नवाचार और प्रयोग आवश्यक

ाज्यपाल जिष्णू देव वर्मा ने कहा कि कौशल विकास, पुनः कौशल (री-स्किलिंग) और कौशल उन्नयन आज की आवश्यकता है। आधुनिक विश्वविद्यालयों को नवाचार और प्रयोगशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करे।

उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का प्रभाव अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ता है। ऐसे में विद्यार्थियों को विविध और प्रासंगिक कौशल सीखने के लिए प्रेरित करना जरूरी है।

राज्यपाल ने यह भी बताया कि इसी लोक भवन के दरबार हॉल में रतन टाटा को ‘डॉक्टर ऑफ लेटर्स’ (डी.लिट.) की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि 18वीं शताब्दी तक भारत व्यापार और कौशल के क्षेत्र में अग्रणी था और उस स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

एआई लिविंग लैब से मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ‘एआई लिविंग लैब’ पहल के माध्यम से छात्रों को उद्योगों की वास्तविक समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और नवाचार क्षमता में वृद्धि होगी।

यह दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत और देश के कौशल विकास अभियान को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

‘भानू अथैया : साधना से सम्मान तक’ सांस्कृतिक कार्यक्रम 27 मार्च को आयोजित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। सांस्कृतिक कार्य विभाग एवं सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई की ओर से भारतीय फिल्म उद्योग की ऑस्कर (अकादमी पुरस्कार) से सम्मानित प्रसिद्ध वेशभूषा डिजाइनर भानू अथैया के जीवन कार्य को श्रद्धांजलि देने हेतु ‘भानू अथैया : साधना से सम्मान तक’ इस विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

यह कार्यक्रम 27 मार्च 2026 को सायं 7:00 बजे रवींद्र नाट्य मंदिर, मुंबई में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य, दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति तथा कथन के माध्यम से भानू अथैया की कला यात्रा और उनकी सफलता की कहानी को प्रस्तुत किया जाएगा। भानू अथैया ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों के लिए वेशभूषा डिजाइन की है। उनके कार्यों में भारतीय परंपरा, गहन अध्ययन तथा ऐतिहासिक सटीकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। वर्ष 1983 में फिल्म ‘गांधी’ के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था और वे यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय थीं। उनकी कला के कारण भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

इस कार्यक्रम में उर्मिला कानेटकर, वैदेही परशुरामी, मानसी नाइक, भार्गवी चिरमुले, किन्नरी दामा, सुकन्या कालन, अभिनय बेर्डे, नकुल घाणेकर, अभिजीत ठाकुर तथा मंगला खाडिलकर जैसे कलाकार भाग लेंगे। कार्यक्रम का नृत्य निर्देशन सुभाष नकाशे एवं मीनल भिके ने किया है, जबकि संहिता लेखन डॉ. सुवर्णा द्वारा किया गया है।

सांस्कृतिक कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एड. आशिष शेलार की संकल्पना तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी के मार्गदर्शन में, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सभी के लिए निःशुल्क खुला है। मुंबई एवं आसपास के नागरिकों, कलाकारों तथा सांस्कृतिक प्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील सांस्कृतिक कार्य संचालनालय के निदेशक श्रीराम पांडे ने की है।

विद्यार्थियों की मेहनत और भविष्य के सपनों का सम्मान – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि रत्न टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह ऐतिहासिक है। आज विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और उनके उज्ज्वल भविष्य के सपनों का सम्मान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश की विकास गति को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख राज्य है और राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्हें यह बताते हुए प्रसन्नता हुई कि औंध स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को अत्याधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि कौशल विभाग की योजनाओं के माध्यम से राज्य में कौशल विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। अत्याधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के 36 स्थानों पर नवदिशा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री महाफंड योजना से प्रतिभाशाली युवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी और उद्यमी

बनने के लिए नए अवसर खुलेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे नई तकनीकों के अनुसार स्वयं को निरंतर विकसित करें। उन्होंने कहा कि युवा देश के समग्र विकास के प्रमुख आधार हैं, इसलिए उन्हें नैतिक मूल्यों के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए। अंत में उन्होंने सभी स्नातकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं, जो अब अपनी डिग्री के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में प्रवेश कर रहे हैं।

‘एआई लिविंग लैब’ पहल से विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों से जोड़ा जाएगा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश का जनसांख्यिकीय लाभ केवल युवा आबादी होने से नहीं मिलता, बल्कि उस आबादी को कौशलयुक्त बनाने से ही वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा आधुनिक तकनीकों (जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विनिर्माण) का प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्किल इंडिया’ अभियान शुरू किया और महाराष्ट्र ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि पहले पूंजी को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब निवेश वहीं जाता है जहां कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौती का सामना करने के लिए समयानुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना जरूरी है। उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण को भी निरंतर अद्यतन करना होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रत्न टाटा

महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय की ‘एआई लिविंग लैब’ जैसी पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योग क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को हल करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है।

उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से 10,000 महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण प्रदान किया है। बदलते रोजगार बाजार को देखते हुए कौशल विश्वविद्यालयों को पारंपरिक विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिक लचीला होना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विश्व में चौथे स्थान से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रही है। इस गति को बनाए रखने के लिए केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि कौशलयुक्त युवा आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि देश में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 31 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र को प्राप्त होता है। यदि महाराष्ट्र एक स्वतंत्र देश होता, तो वह विश्व की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। हाल ही में दावोस सम्मेलन में 30 लाख करोड़ रुपये के समझौते किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दो वर्षों में महाराष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है।

रणवीर सिंह की धुरंधर-2 को बैन करने की मांग, ‘सेंसर बोर्ड ने इसे अनुमति कैसे दी?’

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धर की धुरंधर-2 जहां कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, वहीं इस फिल्म को बैन करने की मांग उठ गई है. कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने ’धुरंधर 2’ को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये गलत फिल्म है और लोगों को भड़काने का काम कर रही है. ये फिल्म लोगों में दरार पैदा करने का काम कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि इस तरह की फिल्म बनाने वाले क्या ये कलाकार हैं? क्या ये कला के बारे में कुछ जानते हैं? ये प्रचार फिल्में बनाते हैं. ये बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. इन्हें पैसे कौन देता है? और सेंसर बोर्ड इन फिल्मों को कैसे पास कर देता है? उन्होंने दावा किया कि फिल्म के लिए बीजेपी ने ही पैसे दिए. ये बीजेपी के टट्टू हैं. इस तरह की फिल्में दिखाकर लोगों में दरार पैदा करना गलत है.

’इस देश में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनीं’

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इस देश में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में

बनी हैं. जैसे- मदर इंडिया, दो बीघा जमीन, इस देश में गंगा बहती है, नया दौर, बंदिनी, इस तरह की फिल्मों ने समाज को जोड़ने का काम किया. समाज की तरफ अच्छा सोचने, समाज की तरफ अच्छा देखिए, ये बताने का काम किया. हिंदुस्तान से अलग पाकिस्तान बनने के बाद भी यहां दरार पैदा करने वाली फिल्में नहीं बनी. देश विकास कैसे करेगा, लोग साथ कैसे रहेंगे, हमेशा ये संदेश दिया गया लेकिन ये टपोरी लोग हैं.

कांग्रेस नेता ने हमला बोलते हुए आगे कहा, ’’बीजेपी ने इसे स्पॉन्सर नहीं किया बल्कि इसने ने ही पैसा दिया है. ये बीजेपी के टट्टू हैं. समाज के खिलाफ राजनीति करने वाले लोगों के लिए प्रचार करने का इनका धंधा है. ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

हुसैन दलवई ने ’धुरंधर 2’ पर बैन की मांग की

हुसैन दलवाई ने ’धुरंधर 2’ पर बैन लगाने की भी मांग की. उन्होंने कहा, ’’इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए और सेंसर बोर्ड ने इसे अनुमति कैसे दी? सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं कुछ कर रही है. ये हर वक्त हिंदू-मुसलमान करते रहते हैं. मुसलमानों ने क्या किया है? मुसलमान इस देश में हैं, वे अच्छे काम करते हैं.’’

गलत काम करने वाले हिंदू भी हैं- हुसैन दलवई

उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा, ’’गलत काम करने वाले हिंदू भी हैं. बेशक, कुछ मुसलमान भी गलत काम करते होंगे. ये महात्मा गांधी का देश है. ये देश बाबा साहेब अंबेडकर का है, ये सावित्रीबाई फुले का देश है. ये सावरकर का देश है क्या? इस तरह की फिल्में दिखाकर लोगों में दरार और द्वेष पैदा करना गलत बात है.’

पुणे में हल्दी के पैकेट से गांजे की तस्करी! पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, 16 किलो जब्त

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के पुणे के पॉश बाणेर इलाके में पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है, यहां हल्दी के पैकेट की आड़ में गांजा बेचने का धंधा चलाया जा रहा था. इस मामले में बाणेर पुलिस ने दो आरोपियों अभिषेक भिका बोरसे और अक्षय भिका बोरसे को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके पास से कुल 16 किलो गांजा बरामद किया गया है.

इस संबंध में पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक, बाणेर इलाके में दो युवक मोटरसाइकिल पर गांजा बेचने आने वाले थे, ऐसी गुप्त जानकारी मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने महानगर पालिका के स्विमिंग पूल के पास जाल बिछाया. संदिग्धों को रोककर पूछताछ करने पर उनके कब्जे से हल्दी के पैकेट बरामद हुए.

पुलिस ने 16 किलो गांजा बरामद किया

इन पैकेटों की जांच के बाद पुलिस भी चौंक गई. क्योंकि हल्दी के नाम पर इन पैकेटों में गांजा छिपाकर रखा गया था. शुरुआत में पुलिस ने घटनास्थल से करीब 3 किलो गांजा जब्त किया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पिंपरी-चिंचवड स्थित अपने घर में और नशीले पदार्थ जमा करने की बात कबूल की. इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारकर 13 किलो गांजा और जब्त किया. इस प्रकार कुल 16 किलो गांजा बरामद किया गया है.

निजी कंपनी में नौकरी करते हैं दोनों आरोपी

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी निजी कंपनी में नौकरी करते हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है और जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वे हल्दी के पैकेटों का इस्तेमाल कर गांजे की बिक्री करते थे. इस मामले की आगे की जांच बाणेर पुलिस कर रही है.

महाराष्ट्र में फिर बिगड़ेगा मौसम, कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट

मुंबई। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राज्य के कई हिस्सों में फिर से तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज दोपहर के बाद मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। नांदेड़, लातूर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, गडचिरोली और चंद्रपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है। इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई

है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मार्च महीने में इस तरह की बारिश ने रबी फसलों और बागवानी को प्रभावित किया है, जिससे किसान चिंता में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 16 मार्च से 20 मार्च के बीच राज्य के 24 जिलों में करीब 51,488 हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से बुलढाणा जिले के चिखली क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के अनुसार, तेज ओलों की वजह से केले के पत्ते फट गए और फसल पर दाग पड़ गए, जिससे उत्पादन घटने की आशंका है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में इसी तरह उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

उद्धव ठाकरे का नया फैसला, एयरपोर्ट और पोर्ट नौकरियों के लिए शिवसेना भवन में शुरू होगा प्रशिक्षण

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत एयरपोर्ट, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के लिए शिवसेना भवन में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उद्धव ठाकरे ने बताया कि बालासाहेब ठाकरे के जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि पहले कई क्षेत्रों में मराठी युवाओं के

लिए अवसर सीमित थे, लेकिन अब उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बदलते समय में एक्सपोर्ट-इंपोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से अवसर बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, इसलिए युवाओं को इन क्षेत्रों के लिए तैयार करना जरूरी है।

इस योजना के तहत शुरुआती चरण में 30 युवाओं की एक बैच तैयार की जाएगी। उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर ले जाकर वास्तविक कार्यों का अनुभव कराया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाणपत्र दिया जाएगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके साथ जुड़े विशेषज्ञ उद्योग की मांग के अनुसार कुशल युवाओं को तैयार करेंगे, ताकि उन्हें सीधे रोजगार मिल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी आर्थिक क्षमता है और यदि युवाओं को सही दिशा और प्रशिक्षण मिले, तो राज्य देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकता है।

इस पहल को युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने और कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सम्पादकीय

बोतलबंद पानी का भारतः सार्वजनिक जल प्रशासन की गहरी विफलता

भारत में बोतलबंद पानी पर बढ़ती निर्भरता केवल उपभोक्ता व्यवहार में आए बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक जल प्रशासन में व्याप्त गहरी और बहुस्तरीय प्रणालीगत समस्याओं की ओर भी स्पष्ट संकेत करती है। कभी जो नल का पानी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी माना जाता था, वही आज अविश्वास, असुरक्षा और असमानता का प्रतीक बनता जा रहा है। शहरों से लेकर कस्बों और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी लोग पीने के लिए प्लास्टिक की बोतलों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाती है, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

आधुनिक भारत में जल संकट को अक्सर वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन या बढ़ती जनसंख्या से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बोतलबंद पानी की लोकप्रियता का मूल कारण इनसे कहीं अधिक गहरा है। असल समस्या यह है कि नागरिकों का भरोसा सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणालियों से लगातार टूटता जा रहा है। नलों से आने वाले पानी की गुणवत्ता पर संदेह, नियमित आपूर्ति का अभाव, और पारदर्शिता की कमी ने लोगों को वैकल्पिक स्रोतों की ओर धकेल दिया है। जब राज्य अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में असफल होता है, तब बाजार उस खाली स्थान को भर देता है–अक्सर मुनाफे की शर्तों पर।

शहरी भारत में बोतलबंद पानी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। महानगरों में तो यह लगभग जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है। कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी बड़े जार और बोतलें आम दृश्य हैं। यह स्थिति विडंबनापूर्ण है, क्योंकि इन्हीं शहरों में सबसे विकसित जल अवसंरचना होने का दावा किया जाता है। यदि इतनी सुविधाओं के बावजूद नागरिक सुरक्षित नल का पानी नहीं पी सकते, तो यह प्रशासनिक विफलता का सीधा प्रमाण है। पाइपलाइन की जर्जर हालत, सीवेज और पेयजल लाइनों का आपस में मिलना, तथा नियमित परीक्षण की कमी–ये सभी समस्याएँ वर्षों से ज्ञात हैं, लेकिन समाधान आधे-अधूरे ही रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग होते हुए भी उतनी ही चिंताजनक है। वहां बोतलबंद पानी का उपयोग अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जैसे-जैसे ग्रामीण बाजारों तक निजी कंपनियों की पहुंच बढ़ रही है, यह निर्भरता वहां भी बढ़ने लगी है। कई इलाकों में भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक या आयरन की अधिकता के कारण लोग स्थानीय जल स्रोतों से डरने लगे हैं। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सामुदायिक नल या हैंडपंप अक्सर या तो खराब रहते हैं या फिर उनका पानी पीने योग्य नहीं होता। ऐसे में जिनके पास आर्थिक क्षमता है, वे बोतलबंद पानी खरीद लेते हैं, जबकि गरीब तबके दूषित पानी पीने को मजबूर रहते हैं। यह स्थिति जल के क्षेत्र में गहरी असमानता को जन्म देती है।

बोतलबंद पानी उद्योग का विस्तार अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक ओर यह उद्योग 'शुद्धता' और 'सुरक्षा' का वादा करता है, वहीं दूसरी ओर इसके नियमन में गंभीर खामियां हैं। कई बार यह पाया गया है कि बाजार में उपलब्ध बोतलबंद पानी भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके बावजूद उपभोक्ता इसे नल के पानी से अधिक सुरक्षित मानते हैं। यह धारणा स्वयं में सार्वजनिक जल संस्थानों की साख पर सवाल है। यदि राज्य द्वारा प्रमाणित और नियंत्रित जल आपूर्ति प्रणाली पर नागरिक भरोसा नहीं करते, तो यह लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता के लिए भी खतरे की घंटी है।

पर्यावरणीय दृष्टि से बोतलबंद पानी पर निर्भरता अत्यंत विनाशकारी है। प्लास्टिक की बोतलें कचरे के पहाड़ में बदल रही हैं। पुनर्चक्रण की दर बेहद कम है और अधिकांश प्लास्टिक अंततः नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। इसके अलावा, बोतलबंद पानी के उत्पादन में भी भारी मात्रा में जल और ऊर्जा की खपत होती है। यानी जिस संसाधन की कमी की बात की जा रही है, उसी का अत्यधिक दोहन करके एक कृत्रिम समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विरोधाभास नीति निर्माताओं की अल्पकालिक सोच को उजागर करता है।

सार्वजनिक जल प्रशासन की समस्याएँ केवल तकनीकी नहीं हैं; वे संस्थागत और राजनीतिक भी हैं। जल प्रबंधन से जुड़े विभाग अक्सर संसाधनों की कमी, कुशल मानवबल के अभाव और आपसी समन्वय की समस्या से जूझते हैं। इसके अलावा, जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवा को राजनीतिक प्राथमिकता भी अक्सर नहीं मिलती। चुनावी घोषणाओं में बड़े बांध, नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं या स्मार्ट शहरों की बातें तो होती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जल आपूर्ति को सुधारने पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप, छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्याएं वर्षों तक अनसुलझी रहती हैं।

निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति भी इस संकट को गहरा कर रही है। जब सार्वजनिक प्रणालियाँ कमजोर होती हैं, तो समाधान के रूप में निजी कंपनियों को आगे लाया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में इससे दक्षता बढ़ी है, लेकिन अक्सर इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो भुगतान कर सकते हैं। पानी जैसे आवश्यक संसाधन का बाजार आधारित वितरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। बोतलबंद पानी इस निजीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जहां स्वच्छ पानी एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक उपभोक्ता वस्तु बन जाता है।

सवालों के घेरे में नीतीश कुमार की विदाई

दो दशकों से बिहार की सत्ता की धुरी रहे नीतीश कुमार की विदाई को लेकर सियासी गलियारों में जितनी हैरत जताई जा रही है, सवाल भी उतने ही उठ रहे हैं। बीस साल से कुछ ज्यादा वक्त से लगातार बिहार की सत्ता में बने रहे नीतीश का सियासी स्वभाव ही सवालों और आश्चर्य की वजह बना है। नीतीश ने जब से सत्ता संभाली है, उन्होंने कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वे सत्ता से दूर हो सकते हैं। बीच में जीतन राम मांझी को नौ महीने के लिए सत्ता सौंपकर संन्यासी और बीतरागी जैसा दिखने की कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन वह सिर्फ दिखावा था। सत्ता का असल सूत्र उनके ही हाथ था। जब लगा कि मांझी उस सूत्र को काट कर स्वाधीन पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस धागे को काट सत्ता खुद थाम ली थी। नीतीश सत्ता को इतनी आसानी से छोड़ देंगे, इस पर आसानी से भरोसा ना करने की वजह उनका अतीत रहा है। कभी जीन विवाद तो कभी किसी दूसरी वजह से उन्होंने अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी को छोड़ उस लालू का हाथ दो-दो बार थाम लिया, जिनके विरोध की बुनियाद पर ही उनकी राजनीति परवान चढ़ी। फिर जब उन्हें लगा कि लालू का साथ उनकी सियासी नैया को डुबो देगा तो फिर बीजेपी की ओर लौटने में भी उन्होंने देर नहीं लगाई। यह सियासी आवाजाही हर हाल में सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की उनकी चाहत का ही प्रतीक लगती है। इसी वजह से उनकी विदाई को सहजता से स्वीकार करना कठिन हो रहा है।

राजनीति का एक चरित्र है। अपने कदमों को लिए वह जिन कारणों को गिनाती है, हकीकत में वे कारण होते ही नहीं। नीतीश ने भी कहा है कि वे चाहते थे कि संसद के दोनों सदनों और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य बनें। विधानमंडल और लोकसभा के वे सदस्य रह लिए हैं, लेकिन राज्य सभा के वे सदस्य कभी रहे नहीं। इसलिए वे बिहार की राजनीति छोड़ राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहे हैं। हो सकता है कि नीतीश की यह चाहत रही हो, लेकिन उनके बिहार को छोड़ने के पीछे का यह सच अधूरा है। विगत दो साल में नीतीश कुमार की जुबान कई बार फिसली है। उनकी हरकतें भी कई बार हास्यास्पद रही हैं। नीतीश की छवि ऐसे गंभीर शख्सियत की रही है, जो नाप-तोलकर बोलता है। इसी छवि ने गाहे-बगाहे फिसलती रही जुबान और उल-जलूल हरकतों के बावजूद उनके प्रति लोगों का सम्मान कम नहीं होने दिया है। इसी छवि के चलते विगत के बिहार चुनाव में एनडीए को भारी जीत भी मिली। लेकिन इसके साथ ही यह भी मान लिया गया कि इन चुनावों के बाद नीतीश की विदाई भी हो सकती है। यह कहना मुश्किल है कि बीजेपी और जनता दल यू ने तय किया हो कि चुनाव बाद नीतीश हट जाएंगे या हटा दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश ने खुद को बिहार से दूर किया है, उससे लगता है कि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच ऐसी समझ विकसित हो चुकी थी। चूंकि इसकी भनक बाहर नहीं लग पाई थी, इसलिए यह बदलाव लोगों को आसानी से पच नहीं रहा।

नीतीश ने जिस जनता दल यू को सींचा-खड़ा किया है, उसका भी चरित्र कुछ-कुछ कांग्रेस की तरह हो गया है। जिस तरह नेहरू-गांधी परिवार कांग्रेस को एक रखने का चुंबक है, नीतीश ही जनता दल यू के लिए उसी तरह के चुंबक हैं। बेशक राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, नीतीश के बेहद करीब हैं। लेकिन इन चारों की समूचे जनता दल यू में स्वीकार्यता नहीं है। जदयू को एक नीतीश रख सकते हैं या उनके

बेटे निशांत। जदयू को एक रखने के लिए निशांत का राजनीति में आना जरूरी है। राजनीति में उनके प्रवेश की अटकलें करीब दो वर्षों से लगाई जा रही हैं। नीतीश की छवि परिवारवाद विरोधी नेता की भी है। बिहार की राजनीति के केंद्र में उन्हें लाने के पीछे लालू के परिवारवाद पर उनका तीखा हमला भी रहा है। ऐसे में नीतीश के बाद सीधे निशांत की ताजपोशी उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती थी, लिहाजा निशांत को उत्तराधिकार सौंपने के लिए ऐसी राह चुनी गई है, जिससे नीतीश को कम से कम नुकसान हो। इसलिए वे दिल्ली में राज्यसभा की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि नीतीश बिहार की सत्ता में नंबर दो की पोजिशन संभालने जा रहे हैं। इस कदम से निशांत को सीधे बिहार की सत्ता मिल भी नहीं रही और जदयू पर पकड़ के लिए मजबूत रस्सी भी थमाई जा रही है।

बिहार इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जीविका दीदियों के खाते में अब तक 18 हजार एक सौ करोड़ दिए जा चुके हैं। दो साल में करीब दो लाख कर्मचारियों की भर्ती के बाद राज्य का वेतन खर्च 70 हजार करोड़ से ज्यादा हो चुका है। पेंशन खर्च पैंतीस हजार करोड़ हो चुका है। राज्य का बजट तीन लाख 67 हजार करोड़ का है। इसमें से पैंसठ फीसद खर्च प्रतिबद्ध खर्च है यानी विकास और योजना पर। राज्य की आर्थिक स्थिति की गड़बड़ी के चलते लालू राज के बाद पहली बार वित्त विभाग को आदेश देना पड़ा है कि कर्मचारियों के वेतन खर्च के अलावा कोई भुगतान ना किया जाए। नीतीश को यह कठिनाई पता है। माना जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता सौंपने के पीछे उनका मकसद यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य के इस आर्थिक संकट को सत्ता के केंद्र में होने के चलते उसे भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि अपने लोगों के हाथ सत्ता होने के चलते बिहार को मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय मदद मिल जाए।

1967 में आठ राज्यों में बनी संविद सरकारों में बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ ने समाजवादी दलों का साथ दिया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल को छोड़ दें तो हर राज्य में समाजवादी दलों की वह सहयोगी रही। समाजवाद के साथ शुरू बीजेपी की यात्रा में धीरे-धीरे समाजवादी दलों का जनाधार छीजता चला गया। इस तरह उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बीजेपी की इस वर्चस्ववादी यात्रा की राह में नीतीश का जनता दल यू और नवीन पटनायक का बीजू जनता दल रोड़ा रहा है। उड़ीसा के पिछले चुनाव में बीजेपी पटनायक को पटखनी दे चुकी है और अब नीतीश कुमार ने खुद ही कुर्सी खाली कर दी है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी का अगुआ बनने का सपना पूरा होने जा रहा है।

नीतीश अब बिहार की सत्ता का अतीत हैं। उनकी उपलब्धियां भी कम नहीं हैं। पहले दो कार्यकाल तक यानी 2015 तक उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। नीतीश की एक और उपलब्धि यह है कि लगातार बीजेपी का साथ होने के बावजूद उन्होंने अपनी सरकार का समाजवादी स्वरूप बचाए रखा। सुशासन और सरकार के समाजवादी स्वरूप के चलते नीतीश की राष्ट्रव्यापी छवि बनी।

नीतीश की छवि तो बनी, लेकिन उन्होंने बिहार से बाहर अपना संगठन खड़ा नहीं किया। एक बार अरूणाचल में जदयू के 11 विधायक चुने गए, लेकिन उन्हें सहेजने में नीतीश की दिलचस्पी नहीं रही। इससे दुखी विधायक एक-एक कर पार्टी छोड़ गए। 2023 में इसी छवि के चलते उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का अहं उनकी राह में आड़े आ गया। अगर कांग्रेस ने अपने नेतृत्व को आगे रखने की चाहत का बलिदान किया होता और नीतीश को संयोजक बना दिया होता, शायद इतिहास अलग होता।

आईसीसी में 'नो हैंडशेक', आईपीएल में पाकिस्तानी?

सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने अबरार अहमद के पुराने पोस्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने भारत से जुड़े सैन्य घटनाक्रमों पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं। इसके बाद कुछ समूहों ने सनराइजर्स ब्रांड के खिलाफ बहिष्कार की मांग शुरू कर दी और कई हैशटैग चलने लगे। अनेक पोस्टों में टीम प्रबंधन और विशेष रूप से काव्या मारन की आलोचना की गई। इस प्रकार एक खिलाड़ी की खरीद का मामला केवल खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक संदर्भों से भी जुड़ गया।

– डॉ. प्रियंका सौरभ

क्रिकेट लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद संवाद और संपर्क का एक माध्यम माना जाता रहा है। कई अवसरों पर यह खेल कूटनीतिक पुल की तरह भी काम करता रहा है, जिसने राजनीतिक मतभेदों के बीच भी दोनों देशों के लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाई। किंतु हाल के वर्षों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, डिजिटल मीडिया की तीखी प्रतिक्रियाएँ और राष्ट्रवादी भावनाओं की तीव्रता ने इस परंपरा को चुनौती देना शुरू कर दिया है।

इसी पृष्ठभूमि में इंग्लैंड की फ्रेंचाइज़ी लीग द हंड्रेड की 2026 की नीलामी में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स द्वारा खरीदे जाने के बाद एक नया विवाद सामने आया। यह टीम भारतीय आईपीएल फ्रेंचाइज़ी सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी मानी जाती है और इसके साथ काव्या मारन का नाम भी जोड़ा जाता है। खेल की एक सामान्य नीलामी का यह निर्णय देखते ही देखते सोशल मीडिया की बहस, राष्ट्रीय भावना और वैश्विक क्रिकेट की स्वायत्तता से जुड़ी बड़ी चर्चा में बदल गया।

मार्च 2026 में आयोजित इस नीलामी में सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को लगभग 1.9 लाख पाउंड में अपनी टीम में शामिल किया। टीम प्रबंधन के अनुसार यह निर्णय पूरी तरह क्रिकेटीय आवश्यकताओं के आधार पर लिया गया था। टीम को मध्य ओवरों में विकेट लेने वाले एक विदेशी स्पिनर की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके प्रमुख स्पिनर आदिल रशीद किसी अन्य फ्रेंचाइज़ी से जुड़ चुके थे। टीम के कोच डेनियल विट्टोरी ने भी स्पष्ट किया कि चयन कई विकल्पों पर विचार करने के बाद किया गया और अबरार टीम की रणनीति के अनुसार सबसे उपयुक्त खिलाड़ी थे। इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशासनिक निकाय इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी यह रुख दोहराया कि लीग में खिलाड़ियों का चयन उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं, बल्कि उनके

प्रदर्शन और टीम की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

हालांकि यह निर्णय जल्द ही विवाद का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने अबरार अहमद के पुराने पोस्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने भारत से जुड़े सैन्य घटनाक्रमों पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं। इसके बाद कुछ समूहों ने सनराइजर्स ब्रांड के खिलाफ बहिष्कार की मांग शुरू कर दी और कई हैशटैग चलने लगे। अनेक पोस्टों में टीम प्रबंधन और विशेष रूप से काव्या मारन की आलोचना की गई। इस प्रकार एक खिलाड़ी की खरीद का मामला केवल खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक संदर्भों से भी जुड़ गया।

भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों को समझे बिना इस विवाद को पूरी तरह समझना कठिन है। दोनों देशों के बीच क्रिकेट लंबे समय से राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखलाएँ भी लगभग समाप्त हो गईं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दोनों टीमें आमने-सामने खेलती रही हैं और इन मुकाबलों में खेल के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना भी तीव्र रूप में दिखाई देती है।

हाल के वर्षों में कुछ मैचों के बाद खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक हाथ मिलाने की रस्म को लेकर भी चर्चा हुई। उदाहरण के तौर पर एक मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के बीच हाथ न मिलाने की घटना मीडिया में चर्चा का विषय बनी। इन घटनाओं ने यह संकेत दिया कि खेल और राजनीति को पूरी तरह अलग रखना हमेशा संभव नहीं होता, विशेषकर तब जब दोनों देशों के संबंध पहले से ही संवेदनशील हों।

इस विवाद को आधुनिक फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट के व्यापक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पिछले एक दशक में क्रिकेट का स्वरूप काफी बदल गया है। आईपीएल, द हंड्रेड और अन्य टी-20 लीगों ने क्रिकेट को एक वैश्विक व्यावसायिक उद्योग का रूप दे दिया है। इन लीगों में खिलाड़ी विभिन्न देशों की टीमों के लिए खेलते हैं और टीम मालिक भी अलग-अलग देशों से आते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों का चयन अक्सर पूरी तरह पेशेवर मानकों के आधार पर किया जाता है। टीमों का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिस्पर्धी संयोजन तैयार करना होता है, न कि राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर निर्णय लेना। सनराइजर्स लीड्स का निर्णय भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।

क्रिकेट के तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो अबरार अहमद का चयन पूरी तरह तार्किक भी माना जा सकता है। आधुनिक सीमित ओवरों के क्रिकेट में लेग स्पिनरों की मांग तेजी से बढ़ी है, क्योंकि वे बल्लेबाजों को चौंकाने और मध्य ओवरों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। अबरार की गेंदबाजी की खासियत उनकी तथाकथित 'मिस्ट्री स्पिन' है, जिसमें पारंपरिक लेग ब्रेक, गुगली और अन्य विविधताओं का मिश्रण होता है। इस प्रकार की गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए अनुमान लगाना कठिन बना देती है। विशेष रूप से टी-20 और 100 गेंदों के प्रारूप में ऐसे गेंदबाज मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू सोशल मीडिया की भूमिका भी है। डिजिटल मंचों ने खेल प्रशंसकों को अपनी राय व्यक्त करने का शक्तिशाली माध्यम दिया है। अब प्रशंसक केवल दर्शक नहीं रहे, बल्कि वे सीधे तौर पर टीमों और खिलाड़ियों पर दबाव भी बना सकते हैं। सनराइजर्स लीड्स के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध–दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं।

कार्यस्थल, महिला स्वास्थ्य और मासिक धर्म अवकाश

- डॉ. प्रियंका सौरभ

मासिक धर्म स्त्री जीवन की एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है, किंतु लंबे समय तक इसे सामाजिक संकोच, मौन और उपेक्षा के दायरे में रखा गया। आधुनिक समय में जब कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता, समावेशिता और संवेदनशील नीतियों की चर्चा तेज हुई है, तब 'अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश' की अवधारणा भी विमर्श के केंद्र में आई है। कई देशों और संस्थानों ने महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान विशेष अवकाश देने की नीतियाँ अपनाई हैं, ताकि वे शारीरिक असुविधा और मानसिक तनाव के समय आराम कर सकें। किंतु यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसी अनिवार्य नीतियाँ वास्तव में कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देती हैं, या फिर अनजाने में रोजगार में लैंगिक भेदभाव को और मजबूत कर देती हैं। इस संदर्भ में इस मुद्दे का आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मासिक धर्म के दौरान कई महिलाओं को शारीरिक पीड़ा, थकान, चक्कर, या हार्मोनल परिवर्तन के कारण मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कार्यस्थल पर निरंतर काम करना उनके लिए कठिन हो सकता है। अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करना है। यह नीति इस बात को स्वीकार करती है कि महिलाओं की जैविक आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं और उन्हें उसी अनुसार कार्यस्थल पर सहूलियत मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से यह नीति लैंगिक संवेदनशीलता का प्रतीक है और महिलाओं के प्रति सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा देती है।

इसके अतिरिक्त, अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश कार्यस्थलों पर लंबे समय से चले आ रहे उस मौन को भी तोड़ने का प्रयास है, जिसमें मासिक धर्म को छिपाने या शर्म की चीज़ माना जाता था। जब संस्थान औपचारिक रूप से इस विषय को स्वीकार करते हैं, तब यह सामाजिक स्तर पर भी एक सकारात्मक संदेश देता है कि मासिक धर्म कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इससे महिलाओं को अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने का साहस मिलता है और कार्यस्थल का वातावरण अधिक मानवीय और संवेदनशील बन सकता है।

कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ऐसी नीतियाँ कार्यस्थलों पर उत्पादकता को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा सकती हैं। जब कर्मचारियों को आवश्यकता के समय आराम मिलता है, तो वे स्वस्थ होकर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। यदि किसी महिला को मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक दर्द या असुविधा है और फिर भी उसे काम करना पड़ता है, तो उसका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अल्पकालिक अवकाश उसे शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित करने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार, स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील नीतियाँ दीर्घकालिक दृष्टि से संस्थानों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं।

हालाँकि, इस नीति के पक्ष में प्रस्तुत इन तर्कों के साथ-साथ इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को भी गंभीरता से समझना आवश्यक है। कई आलोचकों का मानना है कि अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ अनजाने में रोजगार में लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दे सकती हैं। यदि किसी संस्थान को यह लगता है कि महिला कर्मचारियों को हर महीने अतिरिक्त अवकाश देना पड़ेगा, तो वह भर्ती के समय पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे सकता है। विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, जहाँ उत्पादकता और समय-प्रबंधन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ नियोक्ता महिलाओं को 'अतिरिक्त दायित्व' के रूप में देखने लग सकते हैं।

इस दृष्टिकोण से यह भी कहा जाता है कि अनिवार्य अवकाश की नीति महिलाओं को 'कम सक्षम' या 'कम विश्वसनीय' कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। यह धारणा बन सकती है कि महिलाएँ हर महीने कुछ दिनों तक कार्य के लिए अनुपलब्ध रहेंगी, जिससे उनके प्रति नियोक्ताओं का दृष्टिकोण नकारात्मक हो सकता है। परिणामस्वरूप, महिलाओं को उच्च पदों, नेतृत्व की भूमिकाओं या महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अवसर कम मिल सकते हैं। इस प्रकार, जो नीति महिलाओं के हित में बनाई जाती है, वही अनजाने में उनके पेशेवर विकास के रास्ते में बाधा बन सकती है।

एक और महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि सभी महिलाओं का मासिक धर्म अनुभव समान नहीं होता। कुछ महिलाओं को इस दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है, जबकि कई महिलाएँ सामान्य रूप से अपने कार्य कर सकती हैं। यदि अवकाश अनिवार्य बना दिया जाए, तो यह उन महिलाओं के लिए भी लागू होगा जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे यह संदेश जा सकता है कि मासिक धर्म के दौरान हर महिला कार्य करने में असमर्थ होती है, जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 'अनिवार्य' शब्द स्वयं में समस्या पैदा कर सकता है।

इसके अलावा, यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि कार्यस्थलों पर केवल महिलाओं के लिए विशेष अवकाश की व्यवस्था की जाती है, तो यह समानता के सिद्धांत के साथ विरोधाभास पैदा कर सकती है। लैंगिक समानता का मूल विचार यह है कि सभी कर्मचारियों को समान अवसर और समान सम्मान मिले। यदि किसी एक समूह को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, तो दूसरे समूह में असंतोष या असमानता की भावना उत्पन्न हो सकती है। हालांकि यह तर्क पूरी तरह से उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि समानता का अर्थ हमेशा 'समान व्यवहार' नहीं बल्कि 'न्यायसंगत व्यवहार' भी होता है, फिर भी इस दृष्टिकोण को नीति निर्माण में ध्यान में रखना आवश्यक है।

कई देशों के अनुभव भी इस बहस को जटिल बनाते हैं। कुछ स्थानों पर मासिक धर्म अवकाश की नीति लागू होने के बावजूद महिलाओं ने इसका उपयोग कम किया है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनके प्रति नकारात्मक धारणा बन सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल नीति बनाना पर्याप्त नहीं है; कार्यस्थल की संस्कृति और मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि संस्थान का वातावरण संवेदनशील और सहयोगी नहीं है, तो कर्मचारी उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने में संकोच कर सकते हैं।

इस संदर्भ में कुछ विशेषज्ञ 'अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश' के बजाय 'लचीली और वैकल्पिक नीति' का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि कर्मचारियों को यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वे अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार अवकाश ले सकें। उदाहरण के लिए, सामान्य चिकित्सा अवकाश या लचीले कार्य समय की व्यवस्था ऐसी हो सकती है जिसमें महिला कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर घर से काम कर सकें या कुछ समय के लिए विश्राम ले सकें। इस प्रकार की व्यवस्था व्यक्तिगत जरूरतों का सम्मान करती है और साथ ही अनिवार्यता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी कम कर सकती है।

इसके साथ ही, कार्यस्थलों पर मासिक धर्म से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ शौचालय, सैनिटरी उत्पादों की उपलब्धता, और संवेदनशील कार्य वातावरण महिलाओं के लिए अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। कई बार अवकाश से अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि कार्यस्थल ऐसा हो जहाँ महिलाएँ बिना झिझक अपनी आवश्यकताओं के बारे में बात कर सकें और उन्हें आवश्यक सहयोग मिल सके।

वास्तव में, इस पूरी बहस का मूल प्रश्न यह है कि समानता का अर्थ क्या है। क्या समानता का अर्थ यह है कि सभी कर्मचारियों के साथ बिल्कुल समान व्यवहार किया जाए, या फिर यह कि उनकी भिन्न आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें न्यायसंगत सुविधाएँ दी जाएँ? आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि वास्तविक समानता तभी संभव है जब जैविक और सामाजिक अंतर को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाई जाएँ। इस दृष्टि से मासिक धर्म अवकाश का विचार पूरी तरह से अनुचित नहीं है। लेकिन इसे इस प्रकार लागू करना आवश्यक है कि यह महिलाओं को कमजोर या कम सक्षम साबित करने के बजाय उनकी गरिमा और अधिकारों को मजबूत करे।

अंततः यह कहा जा सकता है कि अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा प्रस्तुत करती हैं। एक ओर वे महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और संवेदनशीलता को मान्यता देती हैं, वहीं दूसरी ओर वे अनजाने में रोजगार में लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने का जोखिम भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए नीति निर्माण में संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अनिवार्यता के बजाय लचीली नीतियाँ, जागरूकता, और संवेदनशील कार्यस्थल संस्कृति इस दिशा में अधिक प्रभावी समाधान हो सकते हैं।

समाज और संस्थानों को यह समझना होगा कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं बल्कि जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि कार्यस्थल ऐसी नीतियाँ विकसित करें जो महिलाओं के स्वास्थ्य का सम्मान करें और साथ ही उनकी पेशेवर क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखें, तभी वास्तविक लैंगिक समानता की दिशा में सार्थक कदम उठाया जा सकेगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर रविवार के दिन होने जा रहा बड़ा खेल, नीतीश कुमार से जुड़े हैं इसके तार!

लखनऊ। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। लेकिन उससे पहले ही यूपी में सियासी समीकरण बिगड़ने और बनने की शुरुआत भी हो चुकी है। सियासी दल नए-नए समीकरण बनाने की शुरुआत भी कर चुके हैं। नए समीकरण बनाने की शुरुआत भी कर चुके हैं। और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होने जा रहा है और इसके तार जुड़े हैं बिहार से। दरअसल बिहार में जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया और यह भी हुआ कि अब वह मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। उसके बाद से पूर्व सांसद और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ दी। जेडीयू छोड़ने के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे थे कि वो 22 मार्च को आरएलडी का दामन थाम सकते हैं। अब इस अटकलों को बल केसी त्यागी की तरफ से जारी नए प्रेस रिलीज से मिला है। पूर्व राज्यसभा सांसद की तरफ से जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि 22 मार्च को दिल्ली के मावलंकर हॉल में दोपहर 12:30 बजे एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारत के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी चीफ गेस्ट होंगे।

आपको बता दें कि केसी त्यागी पश्चिमी यूपी से आते हैं और अगर जयंत चौधरी की पार्टी में केसी त्यागी शामिल होते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वह बदल जाएगा। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जयंत चौधरी

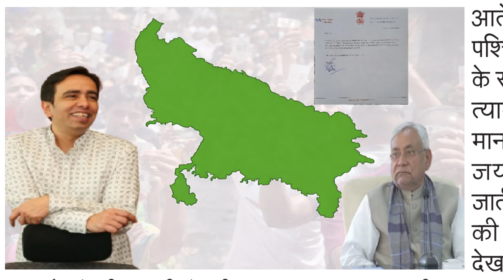

और केसी त्यागी के बीच मुलाकात व बातचीत हुई है। 22 मार्च को संभावित तौर पर केसी त्यागी आरएलडी में शामिल हो सकते हैं। जब उन्होंने जेडीयू छोड़ने का ऐलान किया था तभी कहा था कि 22 मार्च को वह नई दिल्ली से बड़ा ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी वोटर्स का काफी प्रभाव माना जाता है। कई सीटों पर त्यागी वोटर निर्णायक भूमिका में रहता है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्यागी वोटरों की संख्या 10इ के आसपास है। ऐसे में वह हार और जीत का जो अंतर है वह तय करते हैं। इसी वजह से क्या जयंत चौधरी केसी त्यागी को अपनी पार्टी में लाने पर सोच रहे हैं।

केसी त्यागी को दोनों सदनों में कार्य करने का रहा है अनुभव

केसी त्यागी पश्चिमी यूपी से आते हैं। पूर्व में यही इस पश्चिमी यूपी से ही लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं और त्यागी मतदाताओं में प्रभाव माना जाता है। ऐसे में क्या जयंत चौधरी एक नए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा। केसी त्यागी पर जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी में शामिल होने का निर्णय लेते हैं तो उनका स्वागत है। मतलब कि अगर केसी त्यागी शामिल होना चाहते हैं तो जयंत चौधरी खुले दिल से उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। केसी त्यागी वैसे भी चौधरी चरण सिंह की जमकर तारीफ कर चुके हैं। तो इसके बाद से यह बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि केसी त्यागी का नया ठिकाना आरएलडी होगा। साफ़ है कि जयंत चौधरी ने आरएलडी के लिए विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। जयंत चौधरी मौजूदा समय में अपनी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। केंद्र सरकार में वह मंत्री हैं। उनकी पार्टी से कुछ नेता यूपी की योगी सरकार में भी मंत्री हैं।

यूपी के चुनाव में नए समीकरण बनाने में लगे जयंत

दरअसल भाजपा से गठबंधन के बाद आरएलडी से छिड़के मुस्लिमों की भरपाई करने के लिए जयंत चौधरी अब गुर्जर त्यागी ब्राह्मण तथा पिछड़ा समाज के लोगों को साधकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत को आप ऐसे समझिए कि 2022 में जब यूपी में चुनाव हुआ था तो उस वक्त आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। उन चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी को मुस्लिमों का भरपूर साथ मिला। लेकिन जयंत चौधरी को डर है कि अब वो भाजपा के साथ गठबंधन में है तो जब 27 के चुनावी मैदान में वो जाएंगे तब क्या मुस्लिम मतदाता उनके साथ आएगा या नहीं। इसीलिए अब वो नए समीकरण की तैयारी में जुटे हुए हैं।

फाफामऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने दिवंगत हरि मंगल सुनील मिश्रा के परिजनों से मिल जताईशोक संवेदना

प्रयागराज। मांडा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय बामपुर प्रथम में कार्यरत सहायक अध्यापिका वंदना मिश्रा के पति हरि मंगल सुनील मिश्रा (49) के निधन की सूचना पर फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य भाजपा नेताओं के साथ उनके पैतृक गांव पियरी उर्फ बिजलीपुर (लालगोपालगंज) स्थित आवास पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि हरि मंगल मिश्रा एक सरल, विनम्र और समाजसेवी व्यक्ति थे। उनका असमय निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।अधिवक्ता भारत लाल मिश्र के बड़े पुत्र हरि मंगल मिश्रा अपने मिलनसार और सहयोगी स्वभाव के कारण समाज में विशेष पहचान रखते थे। जरूरतमंदों की मदद करना और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। परिवार में उनके छोटे भाई विनय मिश्रा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कार्यरत हैं, जबकि सत्येंद्र मिश्रा भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। सबसे छोटे भाई शिवम मिश्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अपने पीछे वे पत्नी वंदना मिश्रा, पुत्री सौम्या (15) और पुत्र ऐश्वर्य (13) को छोड़ गए हैंइस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक, अधिवक्ता एवं क्षेत्रीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। उपस्थित लोगों में प्रमुख रूप से भारत लाल मिश्रा एडवोकेट, डॉ. रामराज मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा, भीमसेन मिश्रा, गोपाल कृष्ण

मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा, अरुण कुमार शुक्ला कैलाश प्रकाश द्विवेदी, अखिलेश द्विवेदी, विकास द्विवेदी, अभिषेक द्विवेदी, श्याम कृष्ण, पिंटू शुक्ला, भूपेंद्र कुशवाहा सहित तमाम लोग शामिल रहे।

ट्यूबवेल का ताला तोड़कर अनाज चोरी, किसान नेताओं ने थाने पर किया धरना

थरवई थाना क्षेत्र के हसनपुर कोरारी गांव में अज्ञात चोरों ने एक किसान नेता के ट्यूबवेल को निशाना बनाते हुए अनाज चोरी कर लिया।जानकारी के अनुसार गांव निवासी सूर्यमणि शुक्ला घर के पास स्थित ट्यूबवेल पर बने पक्के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने 11 कुंतल गेहूं और 8 बोरी सरसों चोरी कर ली। घटना बीती रात की है।सुबह जब सूर्यमणि शुक्ला ट्यूबवेल की ओर गए तो उन्होंने कमरे का ताला टूटा देखा और अंदर रखा अनाज गायब मिला। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल की और वापस लौट गई।बताया जाता है कि सूर्यमणि शुक्ला नवभारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के प्रदेश अध्यक्ष हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में किसान नेता थरवई थाना पहुंच गए और चोरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। यह धरना करीब ढाई घंटे तक चला।किसानों ने पुलिस से जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। थरवई पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

शांतिपूर्ण ढंग से जनपद में मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार

सिद्धार्थनगर जिले के अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव व अपर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कुमार प्रसाद द्वारा ईद-उल-फितर के पावन अवसर पर थाना डुमरियागंज के विभिन्न मस्जिदों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई नमाज, ईद-उल-फितर पर्व पर पुलिस प्रशासन सतर्क।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम मे, अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सयुक्त रुप से ईद-उल-फितर के पावन अवसर पर थाना डुमरियागंज के विभिन्न मस्जिदों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया । इस दौरान ड्युटी

में तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया । थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सतर्कता बरती जा रही है, जिससे आमजन में सुरक्षा का वातावरण बना रहे तथा ईद-उल-फितर का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके । इस दौरान उपजिलाधिकारी डुमरियागंज, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज व प्राभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज सहित थाना डुमरियागंज के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

'पहले 547 लाख मीट्रिक टन था खाद्यान्न उत्पादन', कृषि मंत्री बोले- 9 वर्षों में 737 लाख मीट्रिक टन हुआ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के देवरिया में शनिवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। इसमें किसानों को सीधा लाभ, सिंचाई विस्तार, उत्पादन वृद्धि और नए कृषि मॉडल स्थापित किया जाना शामिल हैं। सरकार ने न केवल किसानों की आय बढ़ाई, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की दिशा में अग्रसर किया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपहरण, फिरौती, माफियाराज और जंगलराज का बोलबाला था। अब इसे समाप्त किया जा चुका है। 9 वर्ष पहले किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते थे। वे हताश और निराश थे। भय के वातावरण में जी रहे थे। खाद, बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। सरकार किसानों की उपज की खरीद भी नहीं करती थी। गन्ना किसानों का भुगतान तीन-चार साल तक लंबित रहता था। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी।

योगी सरकार ने सबसे पहले किसानों को राहत देने का निर्णय लिया

उन्होंने कहा कि 2017 में योगी सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों को राहत देने का निर्णय लिया गया। 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का बैंक कर्ज माफ किया गया। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक राहत देना नहीं था, बल्कि किसानों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोकना भी था।

कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने उत्कृष्ट बीज उपलब्ध कराने, पर्याप्त खाद की व्यवस्था करने और सिंचाई संसाधनों का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया। 20-30 साल पुरानी नहरों को ठीक कराया गया। अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर 30 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही 92 हजार से अधिक पीएम कुसुम सोलर पंप लगाए गए। इन पर किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया गया। इससे किसानों को सालभर बिना बिजली के निर्बाध सिंचाई की सुविधा मिली।

किसानों की आय में इजाफा हुआ है

उन्होंने बताया कि 16 लाख किसानों के नलकूपों के बिजली बिल माफ किए गए। गन्ना किसानों का लंबित भुगतान जारी किया गया।

हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया उदयपुर थाना पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय भेजा गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में अपराध एवं मयफोर्स द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 190/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352,351(3), 117(2), 109(1) बी.एन.एस. से सम्बंधित सूरज पुत्र लालसा निवासी बकुआव व लाल बचन पुत्र ओरी निवासी बकुआव नफर वांछित

अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल प्रयवेक्षण में शुबेन्दु सिंह क्षेत्राधिकारी बांसी कुशल नेतृत्व मे एवं अभय सिंह थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर अभियुक्तगण को कटया मुख्य मार्ग से उप निरीक्षक अभय सिंह, हेड कांस्टेबल जितेन्द्र सिंह, महिला कांस्टेबल रानी विश्वकर्मा की टीम ने गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कारवाही पूर्ण कर न्यायालय भेजा गया।

दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या करने वाला आरोपी मौसा गिरफ्तार, भेजा गया जेल

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शनिवार को मड़ियांव थाना पुलिस ने नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतका का मौसा लगता है और बरेली का रहने वाला है। इसे कैरियर डेंटल कॉलेज के पास से पकड़ा गया है।

यह है पूरा मामला

चौक निवासी युवक की पत्नी 2016 में किसी दूसरे युवक के साथ चली गई थी। तब से उसके बेटे व बेटी अपने ननिहाल फैजुल्लागंज इलाके में रहते थे। नानी की मौत के बाद मामा-मामी व मौसी उनकी देख-रेख कर रहे थे। इसी बीच मौसी ने बरेली निवासी युवक से

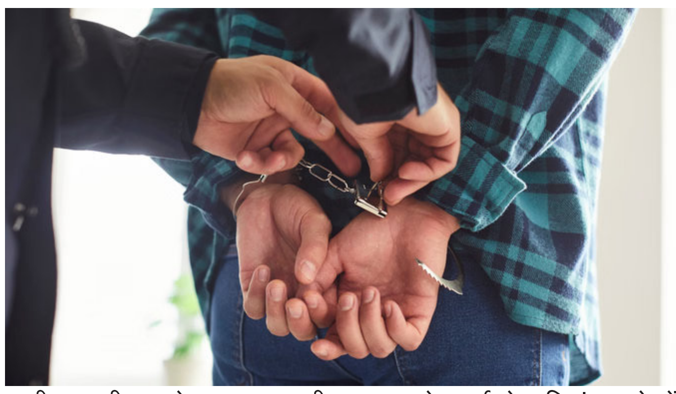

शादी कर ली। इसके बाद युवक भी अपनी पत्नी के साथ रहने लगा।

मृतका के भाई ने मड़ियांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें नाबालिग बहन के साथ अनहोनी की आशंका जताई। भाई के मुताबिक, 18 मार्च की रात बहन को मौसा अपनी बाइक से दवा दिलाने की बात कहकर ले गया था। कुछ देर बाद उसने फोन करके बताया कि रास्ते में कुछ लोगों ने मारपीट करके किशोरी को जबरन कार में बैठाकर ले गए हैं।

नदी किनारे मिले थे किशोरी के कपड़े व चप्पल

सूचना पर परिजन व इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। वहां पर मौसा नशे में धुत मिला। पुलिस ने किशोरी की तलाश में रातभर आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान नदी किनारे किशोरी के कपड़े व चप्पल पड़े मिले। लेकिन, किशोरी का कोई सुराग नहीं लग सका।

19 मार्च को सुबह दोबारा खोजबीन करने पर उसका अर्धनग्न शव पीपा पुल के पास नदी से बरामद किया गया। मृतका के भाई ने मौसा पर दुराचार के बाद हत्या करके शव नदी में फेंकने की आशंका जताई। उसने बताया कि मौसा उसकी बहन पर गलत नजर रखता था। वह पहले भी कई बार गलत हरकत करने का प्रयास कर चुका था।

इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पूर्व में दर्ज एफआईआर में हत्या और पॉक्सो की धारा बढ़ाकर आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

यूपी में मिशन शक्ति अभियान की दिशा में मजबूत कदम, अप्रैल में शुरू होंगे 25 वन स्टॉप सेंटर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए अप्रैल महीने में 25 नए वन स्टॉप सेंटर शुरू होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर की संख्या 96 से बढ़कर 121 हो जाएगी। लखनऊ, जौनपुर, सोनभद्र और नोएडा में सबसे ज्यादा 2-2 नए सेंटर खोले जा रहे हैं। इससे इन जिलों में महिला सुरक्षा तंत्र को अतिरिक्त बल मिलेगा।

इन वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें अल्प प्रवास की सुविधा, चिकित्सकीय सहायता, परामर्श सेवाएं, विधिक सहायता और पुलिस सहयोग शामिल है।

वन स्टॉप सेंटरों न्याय की दिशा में मदद मिल रही है

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए संकटग्रस्त महिलाओं को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने का यह प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है। इससे पीड़ित महिलाओं को त्वरित राहत और न्याय की दिशा में मदद मिल रही है। लखनऊ, जौनपुर, सोनभद्र और गौतमबुद्ध नगर में दो-दो नए केंद्रों के अलावा अयोध्या, मिर्जापुर, महाराजगंज, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, उन्नाव, जालौन, बहराइच, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, चंदौली और हरदोई जैसे जिलों में एक-एक नया वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक वन स्टॉप सेंटर पर आकस्मिक सेवा के लिए एक-एक वाहन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। ताकि, आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।

2.39 लाख मामलों में सहायता

सरकार की यह पहल महिला सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम के रूप में देखी जा रही है। योजना की शुरुआत से अब तक वन स्टॉप सेंटरों पर कुल 2.39 लाख मामलों में सहायता प्रदान की जा चुकी है, जो इसकी उपयोगिता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन व शुबेन्दु सिंह क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण मे अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष थाना खेसरहा मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 24/2026 धारा 108, 352, 351(3) बीएनएस व 3(2)ज्ञ एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र सोहनलाल निवासी महुईनानकार को सेमरा मुस्तकम तिराहे से उप निरीक्षक अनूप कुमार मिश्र, कांस्टेबल अखिलेश कुमार, कॉस्टेबल अजीत कुमार, कांस्टेबल मनोज विश्वकर्मा की टीम ने गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।

डॉक्टर की हत्या करने वाले हैवान को मरते दम तक जेल, 30 साल की सजा के बाद शुरू होगी उम्रकैद

तिरुवनंतपुरम। डॉक्टर वंदना दास की नृशंस हत्या के मामले में केरल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोल्लम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी जी. संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसले की खास बात यह है कि संदीप को पहले अन्य अपराधों के लिए 30 साल की सजा काटनी होगी। इसके बाद ही उम्रकैद की सजा शुरू होगी।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना वर्ष 2023 की है। वंदना दास की हत्या ने केरल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के डॉक्टरों को झकझोर कर रख दिया था। पेशे से शिक्षक जी. संदीप को पुलिस इलाज के लिए कोट्टारक्कारा के तालुक अस्पताल ले गई थी। संदीप ने खुद ही 112 नंबर पर कॉल कर अपनी जान को खतरा बताया था। जब पुलिस उसे घायल अवस्था में अस्पताल लाई, तो वहां अचानक वह हिंसक हो गया।

संदीप ने ड्रेसिंग रूम के मेज पर रखे सर्जिकल कैंची को हथियार बनाया और अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले साथ आए पुलिसकर्मियों पर हमला किया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात युवा डॉक्टर वंदना दास भाग नहीं सकीं। संदीप ने उन पर कैंची से कई वार किए। बुरी तरह घायल

वंदना को तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो मौत को मात नहीं दे पाई।

अदालत में कही गई खास बातें

विशेष लोक अभियोजक प्रताप जी. पडिक्कल ने कहा कि कोर्ट ने संदीप को हत्या, साक्ष्य मिटाने और गलत तरीके से रोकने जैसी आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी पाया है। इसके साथ ही, उसे 'केरल स्वास्थ्य सेवा व्यक्ति और स्वास्थ्य सेवा संस्थान अधिनियम 2012' के तहत भी दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सजा इतनी कठोर हो कि समाज में एक संदेश जाए। अदालत के आदेश के अनुसार, संदीप को पहले 30 साल जेल काटनी होगी। यह सजा उसके पहले के अपराधों के लिए होगा। इसके बाद उसकी वास्तविक उम्रकैद की सजा शुरू होगी।

एक होनहार जीवन का असमय अंत

डॉक्टर वंदना दास कोट्टायम जिले के कडुथुरुथी की रहने वाली थीं। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं। डॉक्टर वंदना अजीजिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाउस सर्जन के साथ ट्रेनिंग के दौरान तालुक अस्पताल में सेवा दे रही थीं। उनकी मौत के बाद केरल में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे।

भिवंडी में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, 90 लाख की संपत्ति नष्ट

राजस्व विभाग का केवणी खाड़ी में अभियान, मशीनरी जलाकर और डुबोकर की कार्रवाई

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी तालुका के केवणी रेत बंदरगाह क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 80 से 90 लाख रुपये की सामग्री नष्ट कर दी। इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। यह विशेष अभियान ठाणे जिला कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल, अपर जिला कलेक्टर हरिश्चंद्र पाटिल और प्रांताधिकारी अमित सानप के मार्गदर्शन में तहसीलदार अभिजीत खोले द्वारा चलाया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर मौजूद 5 सेक्शन और 8 बार्ज को जब्त कर उन्हें जलाकर और पानी में डुबोकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह अवैध रेत कारोबार लंबे समय से चल रहा था। जानकारी के मुताबिक, माफियाओं ने खाड़ी से निकाली गई रेत को जमा करने के लिए किनारे पर 12 बड़ी कुंडियां बना रखी थीं। प्रशासन ने 3 जेसीबी मशीनों की मदद से इन सभी कुंडियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि जिस जमीन (सर्वे नंबर 181/ब) पर रेत जमा की गई थी, वह 'आरक्षित वन' क्षेत्र में आती है। इस कारण वन विभाग और ठाणे मैंग्रोव संरक्षण इकाई ने भी कार्रवाई में भाग लिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भिवंडी ग्रामीण पुलिस की टीम मौके पर तैनात रही। साथ ही खारबाव, पडघा और भिवंडी मंडल के अधिकारी, तलाठी और मैंग्रोव संरक्षण इकाई के कर्मचारी भी इस अभियान में शामिल थे। राजस्व विभाग की इस कड़ी कार्रवाई से रेत माफियाओं को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन का कहना है कि अवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

भिवंडी मे 14 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित, 28 अप्रैल को होगा मतदान

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी।भिवंडी तालुका की विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनावों की घोषणा कर दी गई है। सरपंचों और सदस्यों के निधन, इस्तीफे या अन्य कारणों से खाली हुई 14 ग्राम पंचायतों की सीटों पर अब चुनावी हलचल शुरू हो गई है। भिवंडी के तहसीलदार अभिजीत खोले ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सीटों के लिए मतदान 28 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि मतों की गणना 29 अप्रैल को की जाएगी।प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनावी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होगी। 30 मार्च को तहसीलदार द्वारा आधिकारिक चुनाव नोटिस जारी किया जाएगा।07 अप्रैल से 13 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 15 अप्रैल को नामांकन पत्रों की बारीकी से जांच की जाएगी। 17 अप्रैल को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन। 28 अप्रैल को मतदान का दिन। 29 अप्रैल को मतगणना और परिणामों की घोषणा कि जाएगी। भिवंडी तालुका की जिन 14 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं कवाड खुर्द, पिळंझे खुर्द, मोरणी, गणेशपुरी, सुपेगाव, कारीवली, खरीवली, पालखणे, घोटगाव, कुसापुर, सापे, मोहंडुल, केल्हे और अंबाडी सहित कुल 23 ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के लिए यह चुनाव लड़ा जाएगा। विशेष ऐंम्प यह है कि इसमें 2 सीधे सरपंच पदों के लिए भी मतदान होना है। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।

मुबारकबाद देने ऐशबाग ईदगाह पहुंचे अखिलेश यादव; ईद की खुशियों में घुली सियासत, 2027 का संकेत दिखा साफ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज यानी शनिवार को ईद मनाई जा रही है। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पर मुबारकबाद देने सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। उनके पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई। मौजूद लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने गले मिलकर बधाई दी। लोगों से बात की। ईदगाह से बाहर निकलने पर मीडिया से भी बात की। उन्होंने प्रदेश में ब्राह्मणों के अपमान और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। तंज कसा कि राजधानी में अब

दोबारा बाटी-चोखा की दावत नहीं हो पाएगी। चुटिया पकड़कर खींच लिया गया है। बताइए कितना अपमान हुआ। उधर, राजधानी में शिया समुदाय के लोगों ने खामेनेई की मौत के गम में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनई सहित ईरानी लोगों के मारे जाने के खिलाफ नमाज के बाद अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी भी की।

'मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई लिए खतरा', सोशल मीडिया पर अपलोड पुलिस की वीडियो को लेकर अदालत चिंतित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में सुनवाई के दौरान मोबाइल फोन से शूट किए गए वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने को एक गंभीर समस्या बताया। इसके साथ ही इसे निष्पक्ष मुकदमे के लिए बड़ा खतरा भी बताया। कोर्ट की यह टिप्पणी उस पीआईएल पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस अक्सर आरोपी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिससे जनता के मन में पक्षपात पैदा होता है।

इतना ही नहीं पीआईएल में यह भी कहा गया कि पहले ही राज्यों को मीडिया ब्रीफिंग के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा गया है, जो सोशल मीडिया पोस्ट को भी कवर करेगा। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति मोबाइल फोन के साथ खुद को मीडिया मानने लगा है। बता दें कि यह टिप्पणी सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली भी शामिल थे।

सीजेआई सूर्यकांत ने इसे डिजिटल गिरफ्तारी जैसा बताया

इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने इसे डिजिटल गिरफ्तारी जैसा बताया और कहा कि लोग खुद को मीडिया बताकर अलग तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पीआईएल को फिलहाल वापस ले लिया

जाए और अप्रैल के बाद एसओपी लागू होने के बाद व्यापक दायरे के साथ दोबारा दायर किया जाए। कोर्ट के इस सुझाव को वकील ने मान लिया।

न्यायमूर्ति ने एसओपी बनाने पर दिया जोर

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि केवल पुलिस को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव को रोकना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म केवल ऑनलाइन काम कर रहे हैं और लोगों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि पुलिस कभी-कभी आरोपी को हाथकड़ी में दिखाने, घसीटने या झुकाने जैसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देती है, जो व्यक्तिगत सम्मान और निष्पक्षता के लिए खतरा है।

भिवंडी में उल्लास और भाईचारे के साथ मनाई गई रमजान ईद, लाखों लोगों ने अदा की नमाज

ईदगाह मैदान से लेकर 100 से अधिक मस्जिदों में गूंजे अमन-चैन के पैगाम

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी शहर में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व ईद-उल-फितर (रमजान ईद) इस वर्ष भी पूरे उत्साह, उल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। एक माह तक रोजा रखने के बाद ईद के दिन शहर भर में खुशी और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। ईद के मौके पर सुबह करीब 7 बजे से ही शहर के ईदगाह मैदान सहित लगभग 105 मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया था। नमाज के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पारंपरिक परिधानों में नजर आए। शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ नमाज अदा कर देश में अमन, शांति और समृद्धि के लिए दुआ मांगी।

कोटर गेट स्थित सुन्नी जामा मस्जिद में भी हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने एक साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। कोटर गेट क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे और सहायक पुलिस आयुक्त विजय मराठे स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुलाब के फूल भेंट कर ईद की शुभकामनाएं दीं और भाईचारे का संदेश दिया। ईद के अवसर पर पूरे भिवंडी शहर में उत्सव जैसा माहौल रहा। बाजारों और गलियों में रौनक देखने को मिली। लोग एक-दूसरे के घर जाकर मुबारकबाद देते नजर आए, वहीं बच्चों में खास उत्साह देखा गया।घरों में विशेष पकवान और मिठाइयां बनाई गईं, जिन्हें आपस में बांटकर खुशियां साझा की गईं। ईद के इस पावन अवसर पर भिवंडीवासियों ने धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे का परिचय दिया। लोगों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाया और समाज में सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। कुल मिलाकर, भिवंडी में मनाई गई रमजान ईद ने एक बार फिर शहर की गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक एकता की मिसाल पेश की।

'प्रतिबंध की सिफारिश भारत विरोधी एजेंडा'; 275 पूर्व जज-अफसर अमेरिका से आई रिपोर्ट पर भड़के

नई दिल्ली।कुल 275 पूर्व न्यायाधीशों, लोक सेवकों और सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) की हालिया रिपोर्ट की आलोचना की। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंधन लगाने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने इस रिपोर्ट को 'पूरी तरह प्रेरित' बताया और कहा कि यह 'बौद्धिक दिवालियापन और विकृत सोच' को दर्शाती है।

उन्होंने शनिवार को जारी इस संयुक्त बयान में अमेरिकी सरकार से आग्रह किया कि वह यूएससीआईआरएफ की इस पूर्वाग्रह से भरी रिपोर्ट के सभी योगदानकर्ताओं की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच कराए। उन्होंने आरोप लगाया, कुछ निहित स्वार्थ भारत के लोगों के साथ उनके संबंध खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

संयुक्त बयान में क्या कहा गया?

संयुक्त बयान में कहा गया, 'संपत्तियों को जब्त करने, यूएससीआईआरएफ की भारतीय नागरिकों की आवाजाही को सीमित करने और आरएसएस से जुड़े लोगों पर पाबंदी लगाने जैसी सिफारिशें पूरी तरह प्रेरित हैं। ये सिफारिशें बौद्धिक दिवालियापन और विकृत मानसिकता को दर्शाती हैं।' उन्होंने कहा, 'यूएससीआईआरएफ के सभी छह आयुक्त अमेरिकी सरकार नियुक्त करती है और अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के जरिये से

अमेरिकी करदाताओं के पैसे से वित्तपोषित होते हैं। हम अमेरिकी सरकार से आग्रह करते हैं कि इस रिपोर्ट के योगदानकर्ताओं की पृष्ठभूमि की सख्त जांच कराई जाए।' उन्होंने आगे कहा, इससे अमेरिकी करदाताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनके पैसे का इस्तेमाल ऐसी पूर्वाग्रह से भरी हुई और बेबुनियाद रिपोर्ट बनाने में किया जा रहा है, जिसका मकसद कुछ भारत-विरोधी छिपे हुए एजेंडा को आगे बढ़ाना है। बयान में यह भी कहा गया, यूएससीआईआरएफ कई बार भारतीय संस्थानों और आरएसएस जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को बिना पर्याप्त संदर्भ के नकारात्मक रूप से पेश करता है। इसमें कहा गया, यह प्रवृत्ति विश्लेषण में संतुलन की कमी को दर्शाती है। आरएसएस की जमीनी स्तर पर मजबूत मौजूदगी और समाज सेवा व राष्ट्र निर्माण में योगदान को देखते हुए आलोचना हो सकती है। लेकिन यह ठोस सबूत और सही संदर्भ पर आधारित होनी चाहिए, न अनुमानों के आधार पर लगाए आरोपों पर।

संयुक्त बयान में किन-किन हस्तियों ने हस्ताक्षर किए?

उन्होंने जोर देकर कहा, भारत में मजबूत न्यायिक प्रणाली और धार्मिक अधिकारियों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। बयान में कहा गया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मजबूत और समय-परीक्षिकुल 275 हस्ताक्षरकर्ताओं में 25 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 119 पूर्व नौकरशाह (जिनमें 10 राजदूत शामिल हैं) और 131 सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल (जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं) और हेमंत गुप्ता, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत और सुनील अरोड़ा, पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पूर्व निदेशक योगेश चंद्र मोदी सहित कई सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और सशस्त्र बलों के अधिकारी शामिल हैं। यह संयुक्त बयान पूर्व राजदूत भास्वती मुखर्जी और पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एम मदन गोपाल ने मिलकर तैयार किया। त न्यायिक प्रणाली, सक्रिय लोकतांत्रिक संस्थाएं और संसदीय निगरानी के कारण किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करके बच निकलने की संभावना बहुत कम है।

'ईरान-भारत पाइपलाइन से पीछे हटना थी ऐतिहासिक भूल', केरल के सीएम ने बताई ऊर्जा संकट की वजह

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने देश में गहराते ऊर्जा संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों ने अमेरिकी प्रभाव में आकर ऐसे फैसले लिए, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा आज अधर में लटक गई है।

विजयन ने किया 'ऐतिहासिक गलती' का जिक्र

सीएम विजयन ने कहा कि वर्ष 2006 में भारत ने प्रस्तावित भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना से अपने हाथ खींच लिए थे। यह एक ऐतिहासिक गलती थी। उन्होंने सीधा-सीधा आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर यह कदम उठाया था। अगर यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता, तो आज देश की ऊर्जा जरूरतें सस्ती और सुलभ होतीं।

मणिशंकर अय्यर को लेकर विजयन ने क्या कहा?

विजयन ने तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर को हटाए जाने के मामले को भी दोबारा हवा दी। उन्होंने दावा किया कि अय्यर को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वे पाइपलाइन परियोजना के प्रबल समर्थक थे। उनकी जगह मुरली देवड़ा को लाया जाना इस बात का संकेत था कि सरकार की प्राथमिकताएं 'देश हित' से हटकर 'कॉर्पोरेट हितों' की ओर झुक गई थीं।

वर्तमान सरकार पर विजयन ने साधा भी निशाना

मुख्यमंत्री ने वर्तमान मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज भी नीतियां कुछ खास निजी ऊर्जा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। रूस से कच्चे तेल की खरीद के मामले में भी उन्होंने केंद्र के रुख को ढुलमुल बताया। उन्होंने कहा कि भारत बाहरी दबावों के आगे घुटने टेक रहा है।

विजयन के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आज देश का आम आदमी और उद्योग जगत बर्बादी की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए न तो पर्याप्त 'स्ट्रेटेजिक रिजर्व' बनाए और न ही घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर कोई गंभीर काम किया। अब सरकार को सतर्क होने की जरूरत है।

वर्चस्व बनाने को फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर की थी फायरिंग, आरोपी को एसटीएफ ने आगरा से किया गिरफ्तार

लखनऊ। यूपी एसटीएफ को शनिवार को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने अन्तरराष्ट्रीय कुख्यात अपराधी शुभम लोनकर गैंग के सदस्य प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। यह फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के आवास पर दहशत व रंगदारी के उद्देश्य से की गई फायरिंग के मामले में वांछित चल रहा था।

एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया अभियुक्त प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू, आगरा जिले के बाह थाना क्षेत्र के महावीर नगर पक्की तलैया बिजौली मोहल्ले का रहने वाला है। इसकी उम्र करीब 23 वर्ष बताई जा रही है। इसे महावीर नगर बिजौली से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शुभम लोनकर गैंग के फेसबुक, इस्टांग्राम पर पोस्ट देखकर और उससे प्रभावित होकर वर्चस्व दिखाने की योजना बनाई थी। इससे पहले महावीर नगर मोहल्ला निवासी साथी शिवम दुबे पुत्र अनिल दुबे ने घटना को अंजाम देने के लिए इसे बताया था। शिवम दुबे के कहने पर इसने घटना को अंजाम दिया।

'भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता': पश्चिम एशिया संकट के बीच यूएई के राजदूत बोले- देश पूरी तरह सुरक्षित

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हमलों के बीच भी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत के साथ अपने मजबूत रिश्ते का संदेश दिया है। भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अलशाली ने ईद के मौके पर एक खुला पत्र लिखकर भारत और यूएई के मजबूत रिश्तों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव और हमलों के बावजूद यूएई पूरी तरह सुरक्षित, स्थिर और सामान्य रूप से काम कर रहा है। उन्होंने भारतीय समुदाय को भरोसा दिलाया कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और सुरक्षा, सेवाएं व व्यापार बिना रुकावट जारी हैं।

अब्दुल नासिर अलशाली के इस संदेश के जरिए यूएई ने न सिर्फ अपनी तैयारियों का संकेत दिया, बल्कि भारत-यूएई साझेदारी की मजबूती और भरोसे को भी फिर से रेखांकित किया। पत्र में राजदूत ने बताया कि ईरान ने यूएई पर 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, लेकिन ज्यादातर को देश की रक्षा प्रणाली ने रोक लिया। इसके बावजूद देश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, संचार और खाने-पीने जैसी सभी जरूरी सेवाएं बिना किसी रुकावट के चल रही हैं। होटल, मॉल, पर्यटन स्थल और बैंकिंग व्यवस्था भी सामान्य रूप से काम कर रही है।

यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों पर क्या कहा?

नासिर अलशाली ने कहा कि यूएई में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा भारतीय पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। उनके अनुसार, यूएई ने ऐसी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, जो ऐसे मुश्किल समय में भी देश को स्थिर बनाए रखती है। राजदूत ने भारतीय कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि यूएई में व्यापार पूरी तरह चालू है। सप्लाई चेन, बंदरगाह और एयरपोर्ट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं, जो हर मुश्किल दौर में और मजबूत होते हैं।

यूएई में रहने वाले भारतीयों को बताया अहम हिस्सा

उन्होंने यह भी कहा कि यूएई में रहने वाले भारतीय सिर्फ प्रवासी नहीं, बल्कि इस देश का अहम हिस्सा हैं। वे यहां काम करते हैं, परिवार बसाते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं। कई लोगों के लिए यूएई अब सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि उनका घर बन चुका है। राजदूत ने बताया कि भारत सरकार भी इस पूरे समय में लगातार संपर्क में है और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

भारत और यूएई के बीच व्यापार

बता दें कि भारत और यूएई के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है ।

मनोरंजन

अध्यात्म से ग्लैमर तकः ममता कुलकर्णी का बदला अंदाज़ चर्चा में

मुंबई। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जो कभी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही हैं और बाद में आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ी थीं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वर्ष 2025 के महाकुंभ मेले में 'महामंडलेश्वर' के रूप में दिखाई देने के बाद अब उन्होंने अपने साध्वी रूप से अलग एक नया ग्लैमरस अवतार अपनाया है।
हाल ही में ममता कुलकर्णी गोवा में अपने मित्रों के साथ अवकाश मनाती नजर आईं। सोशल मीडिया पर उनके गोवा प्रवास के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में वे भगवा वस्त्रों के बजाय अपने पुराने फिल्मी अंदाज़ में दिख रही हैं और समुद्र तट पर दोस्तों के साथ आनंद लेते हुए स्वयं वीडियो बनाती

नजर आ रही हैं।
करीब 25 वर्षों बाद भारत लौटी ममता इससे पहले एक कार्यक्रम के मंच पर भी दिखाई दी थीं, लेकिन गोवा में उनके इस नए रूप ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है।
सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
उनके इस बदले हुए अंदाज़ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या उन्होंने आध्यात्मिक जीवन त्याग दिया है, तो कुछ ने उनकी आलोचना भी की। वहीं, कई प्रशंसकों ने उनके गले में रुद्राक्ष देखकर यह माना कि उनका आध्यात्म से जुड़ाव अभी भी बना हुआ है।
ममता कुलकर्णी के इस नए रूप ने एक बार फिर उनकी लोकप्रियता को बढ़ा दिया है। उनके प्रशंसकों के बीच यह उत्सुकता बनी हुई है कि वह आगे किस परियोजना में नजर आएंगी और यह नया अंदाज़ कितने समय तक जारी रहेगा।

सई के लिए बड़े बदलाव का मौका!

प्री-इंडिपेंडेंस दौर पर आधारित पीरियड ड्रामा की तैयारी कर रही हैं सई एम. मांजरेकर

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री सई एम. मांजरेकर प्री-इंडिपेंडेंस दौर पर आधारित पीरियड ड्रामा की तैयारी कर रही हैं। सई एम. मांजरेकर जल्द ही एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं, जो आज के समय से बिल्कुल अलग है। वह एक प्री-इंडिपेंडेंस दौर पर आधारित पीरियड ड्रामा की तैयारी कर रही हैं। यह प्रोजेक्ट उनके लिए एक बड़ा बदलाव है। सई का कहना है कि इस फिल्म की तैयारी काफी गहन, चुनौतीपूर्ण और उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव रही है। फिल्म के बारे में बात करते हुए सई ने बताया कि इस किरदार ने उन्हें एक्टिंग को एक अलग नज़रिए से समझने के लिए प्रेरित किया है।

उस दौर के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को समझने से लेकर अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और हाव-भाव बदलने तक, उन्होंने इस किरदार के लिए काफी रिसर्च और मेहनत की है ताकि वह उस समय को सही तरीके से पर्दे पर दिखा सकें। अपने अनुभव के बारे में सई ने कहा, 'यह प्रोजेक्ट मेरे लिए अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक यात्राओं में से एक रहा है। खासकर प्री-इंडिपेंडेंस दौर पर आधारित पीरियड ड्रामा के लिए सिर्फ डायलॉग याद करना और सेट पर पहुंच जाना काफी नहीं होता।
इसमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है - उस समय के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, यह समझना कि लोग कैसे रहते थे, कैसे बात करते थे, कैसे खुद को प्रस्तुत करते थे और अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करते थे। उस दौर में हर चीज़ एक अलग अनुशासन और सादगी से जुड़ी होती थी, जो आज की दुनिया से काफी अलग है।' सई ने कहा, 'मुझे सबसे ज़्यादा इस प्रक्रिया की बारीकियां आकर्षित करती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बैठने-उठने का तरीका, कमरे में प्रवेश करने का अंदाज़ या बिना कुछ कहे प्रतिक्रिया देना - कुछ भी आधुनिक नहीं लगना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी कई आदतों को छोड़कर एक नई शारीरिक और भावनात्मक शैली अपनानी पड़ती है। यह मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यही इसे खास बनाता है। एक अभिनेता के तौर पर मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला, जो मुझे एक अलग दौर को समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका दे रही है।' इस प्रोजेक्ट को लेकर सई काफी उत्साहित हैं और उनका मानना है कि इस फिल्म ने उन्हें धैर्य, अनुशासन और अभिनय के कई अहम पहलू सिखाए हैं। अब वह इस फिल्म के जरिए इतिहास से जुड़ी कहानी को पूरी सच्चाई और गहराई के साथ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है।

संदीपा धर को 'चुंबक' की शूटिंग के दौरान नीना गुप्ता से मिली खास सीख

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री संदीपा धर ने अपनी आगामी नेटफ्लिक्स श्रृंखला 'चुंबक' की शूटिंग के दौरान वरिष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता से मिली एक खास सलाह साझा की है। संदीपा के अनुसार, काम और किस्मत को लेकर नीना गुप्ता का नजरिया उनके लिए बेहद प्रेरणादायक साबित हुआ।
इस अनुभव को याद करते हुए संदीपा ने बताया कि नीना गुप्ता अक्सर कहती हैं कि उन्होंने एक छोटी-सी छात्र फिल्म में काम किया था, और उसी के कारण उन्हें आगे चलकर फिल्म 'बधाई हो' जैसी बड़ी सफलता मिली। उनका मानना है कि कौन-सी फिल्म कौन देखेगा और कब अवसर मिल जाएगा, यह पहले से तय नहीं होता। इसलिए एक कलाकार का काम सिर्फ लगातार मेहनत करना और अच्छा काम करते रहना है, ताकि किसी न किसी मौके पर सही लोग उसे देख सकें।
नीना गुप्ता की यह सलाह उनके अपने जीवन अनुभव और संघर्ष को भी दर्शाती है, जहां निरंतर प्रयास और जुनून ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। संदीपा धर के लिए इस सीख का सार यही है कि परिणाम की चिंता छोड़कर अपने हुनर और काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
आज के दौर में, जहां तुरंत सफलता पाने की चाह बढ़ गई है, 'बस काम करते रहो' जैसी सीख बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक मानी जा रही है। हाल ही में संदीपा धर फिल्म 'दो दीवाने शहर में' में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ प्रभावशाली भूमिका निभाई। अब वे पहली बार नीना गुप्ता के साथ 'चुंबक' में दिखाई देंगी। हालांकि इस श्रृंखला के बारे में अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों कलाकारों के बीच की यह प्रेरक बातचीत दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा रही है।

आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन से नाराज अश्विन, केकेआर को दी सैलरी काटने की सलाह

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल में अपनी पूरी भूमिका नहीं निभाता, तो फ्रेंचाइजी को उसके कॉन्ट्रैक्ट से पैसे काटने का अधिकार होना चाहिए।
25.20 करोड़ की कीमत पर केकेआर ने ग्रीन को खरीदा
आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की ओर से खेल रहे ग्रीन पर इस सीजन सबकी नजरें रहेंगी। ग्रीन को मिनी ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, जिससे वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। हालांकि, हाल के समय में उनके फॉर्म और गेंदबाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
अश्विन ने केकेआर को दी सैलरी काटने की सलाह
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'एश की बात' पर कहा कि केकेआर और टीम के सह-मालिक शाहरुख खान को निराशा होगी अगर ग्रीन हर मैच

में पूरे चार ओवर गेंदबाजी नहीं करते। अश्विन ने सवाल उठाया, 'क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ग्रीन को हर मैच में चार ओवर फेंकने की अनुमति देगा? अगर नहीं, तो फ्रेंचाइजी को नुकसान होगा।' उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ एक या दो ओवर ही गेंदबाजी करता है, तो टीम को उसके कॉन्ट्रैक्ट से रकम काटने का अधिकार मिलना चाहिए। अश्विन के अनुसार, 'जब टीम ने 25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, तो उम्मीद भी पूरी होनी चाहिए। अगर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो पैसे काटना जायज है।' केकेआर को इस सीजन अपने गेंदबाजी आक्रमण में कुछ चोटों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में ग्रीन की गेंदबाजी टीम के लिए बेहद अहम हो सकती है।
केकेआर के लिए नहीं कम हो रही मुश्किलें
तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए और अब एक अन्य तेज गेंदबाज आकाश दीप भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आकाश दीप चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। खिलाड़ियों की चोट का सबसे ज्यादा प्रभाव केकेआर पर ही पड़ा है।
मुंबई के खिलाफ शुरू करेगी अभियान
आईपीएल 2026 का सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन केकेआर पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर्षित और आकाश दीप जहां पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो वहीं, श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिला है। यह तय है कि वह भी शुरुआती कुछ मैचों में केकेआर के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। आईपीएल में केकेआर अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिनेमा का महाकुंभ, अनुपम खेर को 'आइकन' सम्मान!

कैनबराः ऑस्ट्रेलिया में भारत के बाहर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े राष्ट्रीय उत्सव 'नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया' (एनआईएफएफए) 2026 में इस बार दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर, निर्देशक अनुभव सिन्हा और लीना यादव को सम्मानित किया जायेगा। खेर को 'इंटरनेशनल इंडियन सिनेमा आइकन अवॉर्ड' दिया जायेगा तो सिन्हा और यादव को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

अनुपम खेर ने मिलने वाले सम्मान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया उनके दिल के बेहद करीब है और वह वहां के लोगों में भारतीय कहानियों के प्रति वास्तविक जिज्ञासा देखते हैं। महोत्सव में उनकी निर्देशित फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' की विशेष स्क्रीनिंग भी होगी, जो ऑटिज्म (विकलांगता) जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित है। इस दौरान फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शुभांगी दत्त भी मौजूद रहेंगी।
इस साल महोत्सव में पंजाबी सिनेमा पर खास जोर दिया गया है। इसके लिए 'पीटीसी नेटवर्क' की सीईओ राजी शिन्दे के नेतृत्व में फिल्म निर्माताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। महोत्सव के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन पंजाबी फिल्मों के सह-निर्माण की घोषणा भी की जायेगी।
इसके अलावा, भारतीय दर्शकों के बीच लोकप्रिय शॉर्ट फिल्मों और माइक्रो ड्रामा पर 'पॉकेट फिल्म्स' के सीईओ समीर मोदी मास्टरक्लास भी लेंगे।
मेलबर्न के प्रसिद्ध फेडरेशन स्क्वायर पर 22 मार्च को रात 8 बजे एक मुफ्त सार्वजनिक स्क्रीनिंग का भी आयोजन किया जाएगा।

48 वर्ष की हुई बॉलीवुड की मर्दानी रानी मुखर्जी! रानी ने अपने सधे हुए अभिनय से दर्शकों का ही नहीं बल्कि समीक्षकों का भी दिल जीता

मुंबई। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रानी मुखर्जी 48 वर्ष की हो गई। मुंबई में 21 मार्च 1978 को जन्मीं रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत वर्ष 1997 में प्रदर्शित फिल्म राजा की आयेगी बारात से की। फिल्म हालांकि टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई लेकिन रानी ने अपने संजीदा किरदार के जरिये दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्ष 1998 रानी के करियर के लिए महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ।
इस वर्ष उन्हें आमिर खान के साथ गुलाम और शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है में काम करने का अवसर मिला। दोनों ही फिल्में टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। कुछ कुछ होता है के लिए रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2002 तक का वर्ष रानी मुखर्जी के करियर के लिये बुरा साबित हुआ। इस दौरान रानी मुखर्जी की हैलो ब्रदर, बादल, हर दिल जो प्यार करेगा, हद कर दी आपने, बिच्छू, कहीं प्यार ना हो जाये, चोरी चोरी चुपके चुपके, बस इतना सा ख्वाब है, प्यार दीवाना होता है और मुझसे दोस्ती करोगे जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई लेकिन इन फिल्मों को टिकट

खिड़की पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।
वर्ष 2002 में प्रदर्शित यश राज बैनर तले बनी फिल्म साथियां रानी मुखर्जी के करियर की हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में रानी की जोड़ी विवेक ओबेराय के साथ काफी पसंद की गयी। वर्ष 2003 में प्रदर्शित फिल्म चलते-चलते में रानी को एक बार फिर से किंग खान शाहरूख खान के साथ काम करने का अवसर मिला। यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई।
वर्ष 2004 रानी के करियर के लिये महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी युवा, हमतुम और वीर जारा जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई।
इन सभी फिल्मों में रानी ने अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय दिया और अपने निभाये किरदारों के जरिये दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्ष 2005 में प्रदर्शित फिल्म 'ब्लैक' रानी मुखर्जी के करियर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रानी मुखर्जी को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अवसर मिला। रानी ने अपने सधे हुए अभिनय से न सिर्फ दर्शकों का बल्कि समीक्षकों का भी दिल जीत लिया।

केकेआर के लिए नहीं कम हो रही मुश्किलें, हर्षित के बाद आकाश दीप भी आईपीएल के पूरे सीजन से हुए बाहर

कोलकाता। तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए और अब एक अन्य तेज गेंदबाज आकाश दीप भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आकाश दीप चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। खिलाड़ियों की चोट का सबसे ज्यादा प्रभाव केकेआर पर ही पड़ा है।
मुंबई के खिलाफ शुरू करेगी अभियान
आईपीएल 2026 का सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन केकेआर पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर्षित और आकाश दीप जहां पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो वहीं, श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिला है। यह तय है कि वह भी शुरुआती कुछ मैचों में केकेआर के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। आईपीएल में केकेआर अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी।
केकेआर के पास विकल्प कम

खिलाड़ियों की चोटों ने आईपीएल टीमों की चिंता बढ़ा दी है। 28 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले हर्षित राणा और आकाश दीप समेत पांच खिलाड़ी पूरे सत्र से बाहर हो गए हैं। खिलाड़ियों के बाहर होने का सबसे ज्यादा असर हैदराबाद और कोलकाता पर पड़ा है। हर्षित राणा पहले से ही बाहर थे और अब टीम को आकाश दीप की सेवाएं भी नहीं मिल सकेंगी। केकेआर के पास फिलहाल वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी ही भारतीय तेज गेंदबाज के तौर पर उपलब्ध हैं। हालांकि, टीम के पास कुछ ओवर कराने के लिए ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन उपलब्ध रहेंगे।
आकाश दीप का आईपीएल करियर
आकाश दीप ने 2022 में आईपीएल में डेब्यू किया था और वह अब तक 14 मैच ही खेल चुके हैं। आईपीएल में आकाश दीप के नाम 10 विकेट हैं। पिछले सीजन वह लखनऊ सुपर जाएंट्स का हिस्सा थे जिन्होंने आकाश दीप को 2025 के लिए हुई नीलामी में आठ करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन एक सीजन के बाद ही रिलीज कर दिया था। 29 वर्षीय बंगाल के तेज गेंदबाज को केकेआर ने पिछले साल हुई मिनी नीलामी में एक करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर खरीदा था।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधरः द रिवेंज कमाई ने 145 करोड़ की कमाई की

मुंबईः बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधरः द रिवेंज कमाई ने 145 करोड़ की कमाई कर ली है। आदित्य धर के निर्देशन बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की सीक्वल धुरंधरः द रिवेंज का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पेड प्रीव्यू के दौरान 18 मार्च को फिल्म ने 43 करोड़ रूपये की कमाई की। सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार 'धुरंधरः द रिवेंज' ने रिलीज के पहले दिन 102.55 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म ने 145.55 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
फिल्म की कमाई का मुख्य विवरण नीचे दिया गया हैः
ओपनिंग डे कलेक्शन (भारत नेट): 145.55 करोड़ (इसमें ?43 करोड़ पेड प्रिव्यू के शामिल हैं)।
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन (डे 1): 236 करोड़ से अधिक।
दूसरे दिन की कमाई (अनुमानित): शुक्रवार को फिल्म ने लगभग ?80-82 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे दो

दिनों का कुल भारत नेट कलेक्शन 226-227 करोड़ के पार पहुंच गया है।
प्रमुख रिकॉर्डः यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हिंदी ओपनर बन गई है और इसने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर. माधवन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं।

पहचान की राह में मिला पिता संजय का साथ, नई शुरुआत के बाद भावुक अनाया बोलीं- सफर आसान नहीं था

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच संजय बांगड़ की ट्रांसजेंडर बेटी अनाया बांगड़ ने अपनी जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अनाया ने सोशल मीडिया के जरिए यह खुशखबरी साझा करते हुए बताया कि वह फिलहाल रिकवरी के दौर में हैं और धीरे-धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रही हैं। अनाया ने अपने पोस्ट में डॉक्टरों और अस्पताल की टीम का आभार जताते हुए लिखा कि यह उनके जीवन की एक लंबी और भावनात्मक यात्रा का बेहद अहम पड़ाव है। उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अब वह इस बदलाव को लेकर संतुष्ट और आभारी महसूस कर रही हैं।
पांच साल की तैयारी और आत्ममंथन के बाद फैसला
अनाया पहले ही स्पष्ट कर चुकी थीं कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया था। उन्होंने करीब पांच साल तक इस सर्जरी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार किया। इस दौरान उन्होंने थेरेपी, मेडिकल जांच और गहन आत्ममंथन से गुजरते हुए यह महसूस किया कि वह अपने जन्म के जेंडर से खुद को जुड़ा हुआ नहीं पातीं। ऐसे में यह सर्जरी उनकी असली पहचान को स्वीकार करने की दिशा में एक बड़ा

कदम बनी।
परिवार का साथ बना सबसे बड़ी ताकत
इस पूरी यात्रा में उनके परिवार का साथ बेहद अहम रहा। अनाया ने अपने भावुक पोस्ट में लिखा कि यह सफर सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के लिए भी आसान नहीं था। समझने, स्वीकार करने और उनके साथ खड़े रहने में समय लगा। शुरुआत में कई सवाल, उलझनें और भावनात्मक दौर आए, लेकिन धीरे-धीरे परिवार ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लिया।
उन्होंने खास तौर पर अपने पिता संजय बांगड़ का जिक्र करते हुए कहा कि उनका साथ उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना। अनाया ने लिखा कि पिता का समर्थन तुरंत नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो वह सच्चा, मजबूत और बिना शर्त था। इस सर्जरी के दौरान उनका साथ होना उनके लिए बेहद मायने रखता है।
भावनात्मक पोस्ट में जताया आभार
अनाया ने अपने पोस्ट में लिखा, 'यह सफर आसान नहीं था। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार के लिए भी। समझने और स्वीकार करने में समय लगा। लेकिन आज मैं सिर्फ आभार से भरी हूं। अपने जीवन के सबसे अहम पलों में पिता का साथ होना मेरे लिए सबकुछ है। उनका समर्थन धीरे-धीरे आया, लेकिन जब आया तो पूरी मजबूती के साथ आया।' उन्होंने आगे कहा कि यह सर्जरी उनके लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन पिता के साथ होने से यह संभव लगने लगा। अंत में उन्होंने लिखा कि बदलाव और प्यार दोनों को समय लगता है, लेकिन जब मिलता है तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है।

पश्चिम रेलवे
मरम्मत कार्य
AEE (आर.एस.) बी.एल., विद्युत लोको शेड, पश्चिम रेलवे, वलसाड 396001 (गुजरात) द्वारा ई-निविदा सूचना संख्याः EL/TRS/BL/24-25/WO/21R1, दिनांक 14.03.2026 आमंत्रित की जाती है। **कार्य एवं स्थानः** कार्य - सैंड बॉक्स एवं उसके सहायक उपकरणों का पूर्ण रखरखाव एवं मरम्मत, सैंड बॉक्स में रेत भरना तथा वीसीबी, बीवी बॉक्स, छत की सीटिंग, दरवाजा, खिड़की आदि के गैस्केट का प्रतिस्थापन एवं सभी प्रकार के लोको के लिए ELS/BL में छत चैनल की मरम्मत, अवधि 2 वर्ष। **कार्य की अनुमानित लागतः** 48,71,180.56 **ईएमडी (जमानत राशि):** 97,400/- **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः** 10.04.2026, दोपहर 12:00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि एवं समयः** 10.04.2026, दोपहर 12:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। 1236
हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

नोटिस
DSP MUTUAL FUND
एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आगामी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ('आईएपी') का आयोजन डीएसपी म्यूच्युअल फ़ंड द्वारा किया जाएगा. आईएपी का विवरण निम्नअनुसार है :

दिन व दिनांक	पता	समय
Sunday, 22nd March 2026	Prasad Food Divine, C, Baban Smruti, Y K Nagar, Opposite Reliance Smart, Virar, Mumbai	11:30 AM

सभी आईएपीज़ के बारे में ताजा जानकारी के लिए dspim.com/IAP पर विजिट करें तथा अन्य सभी प्रकटीकरणों के लिए dspim.com/IEID पर विजिट करें. डीएसपी म्यूच्युअल फ़ंड द्वारा निवेशकों की जानकारी तथा जागरुकता हेतु एक पहल. **म्यूच्युअल फ़ंड में निवेशों के साथ मार्केट के जोखिम होते हैं ,स्कीम से संबंधित सभी कागजातों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.**

सीएम सुक्खू ने अपनी सैलरी पर चलाई कैंची, मंत्रियों-विधायकों का भी वेतन कटेगा

शिमला। खर्च में भारी कटौती करते हुए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में छह महीने की देरी की घोषणा की, साथ ही कुल बजट में 3,586 करोड़ रुपये की कटौती भी की। राज्य विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों से सहयोग मांगा और कहा कि राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।
केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने के बाद उत्पन्न हुई 'असाधारण वित्तीय चुनौतियों' को दर्शाते हुए, कुल बजट आवंटन 2025-26 के 58,514 करोड़ रुपये से घटकर 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये हो गया है। सुक्खू ने कहा, 'हम राज्य और इसकी जनता के लिए काम कर रहे हैं, चुनावों के लिए नहीं। मैं सभी वर्गों से छह महीने का सहयोग चाहता हूं और आश्वासन देता हूं कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।
खर्च पर कड़े नियंत्रण के उपायों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके वेतन का 50इ, मंत्रियों के वेतन का 30इ और विधायकों के वेतन का 20इ छह महीने के लिए स्थगित किया जाएगा। वहीं, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव और डीजीपी रैंक

के वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में 30इ और अन्य अधिकारियों के वेतन में 20इ की कटौती की जाएगी। एडीजीपी से डीआईजी रैंक तक के पुलिस अधिकारियों के वेतन में भी 30इ की कटौती होगी, एसपी रैंक के अधिकारियों के वेतन में 20इ और अन्य कर्मचारियों के वेतन में 20इ की कटौती होगी। कर्मचारियों के लिए निर्धारित 3इ वेतन वृद्धि को भी छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है, और इस दौरान ग्रुप डी कर्मचारियों को यह वृद्धि नहीं मिलेगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि वह इसी तरह के स्वैच्छिक वेतन स्थगन उपायों के लिए न्यायपालिका से अपील कर सकती है। बजट प्रस्तुति के दौरान व्यवधान उत्पन्न हुआ, विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और सदन के वेल में प्रवेश किया, जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ और कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। लगभग 30 मिनट बाद कार्यवाही पुनः शुरू हुई और मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन जारी रखते हुए लगभग चार घंटे तक 134 पृष्ठों का बजट भाषण पढ़ा। राजस्व संबंधी चिंताओं को उजागर करते हुए, सुखु ने आरडीजी को बंद करने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और इसे एक बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा, 'हमें हरित लाभ मिलना चाहिए था। इसके बजाय, राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया गया है, जिससे राज्य पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।' उन्होंने बीबीएमबी और जीएसटी मुआवजे के तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाया, जीएसटी युक्तिकरण के कारण अनुमानित 25,000 करोड़ रुपये के नुकसान और बढ़ते ऋण भार का भी मुद्दा उठाया और जोर देकर कहा कि सरकार लोकलुभावन निर्णयों से दूर रहकर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। वित्तीय बाधाओं के बावजूद, सरकार ने चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित 300 से अधिक विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की। साथ ही, एक लाख गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 'मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना' शुरू की गई, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और चरणबद्ध वित्तीय सहायता शामिल है।

ईद पर जम्मू-कश्मीर में सियासत तेज, महबूबा मुफ्ती के बयान पर विवाद

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में ईद के मौके पर राजनीतिक माहौल गरमाता नजर आया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस अवसर पर फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के लोगों के लिए दुआ की, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।
आलोचकों का आरोप है कि उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी हमलों से प्रभावित लोगों और वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
इस बीच, कश्मीर में ईद-उल-फितर पारंपरिक उत्साह के साथ मनाई गई। डल झील के किनारे स्थित हजरतबल दरगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और एक-दूसरे को बधाई दी।
बताया गया कि यहां 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने सामूहिक नमाज में हिस्सा लिया।
हालांकि, श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में इस बार भी ईद की नमाज की अनुमति नहीं दी गई। क्षेत्र में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी, जिससे लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो सके।
कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार सातवें वर्ष भी जामा मस्जिद में ईद की नमाज पर रोक लगाई गई है, जिससे खुशी का दिन गम में बदल गया है।
वहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस फैसले पर अफसोस जताया और कहा कि लोगों को धार्मिक अवसरों पर प्रार्थना की अनुमति मिलनी चाहिए।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच, ईद का त्योहार जहां एक ओर धार्मिक आस्था और उल्लास का प्रतीक रहा, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी और विवादों के कारण चर्चा का केंद्र भी बना रहा।

पुडुचेरी में चुनावी घमासान तेज, भाजपा ने जारी की 9 उम्मीदवारों की पहली सूची

पुडुचेरी। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिससे पार्टी की चुनावी रणनीति स्पष्ट हो गई है।
जारी सूची के अनुसार, पुडुचेरी के गृह मंत्री ए. नमास्सिवयम को मन्नादिपेट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा, पीएमएल कल्याणसुंदरम को कलापेट, जीएनएस राजशेखरन को थिरुनल्लर, वीपी रामलिंगम को राजभवन और ए. जॉनकुमार को मुदलियारपेट से चुनाव मैदान में उतारा गया है।
अन्य उम्मीदवारों में आर. सेल्वम (मनावेली), टीकेएसएम मीनाचिसुंदरम (नेरावी-टीआर पट्टिनम), ए. दिनेशन (माहे) और ई. थेप्पैन्थन (ओसुडु - अनुसूचित जाति आरक्षित सीट) शामिल हैं।
यह घोषणा एआईएनआरसी के साथ हुए सीट बंटवारे के समझौते के बाद की गई है, जिसमें एआईएनआरसी 16 सीटों पर और भाजपा 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने अपने हिस्से की कुछ सीटें एआईएडीएमके और लक्ष्य जननायगा काची (एलजेके) को भी आवंटित की हैं।
इससे पहले पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और एआईएनआरसी नेता एन. रंगासामी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बैठक कर गठबंधन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था।

पिछले चुनाव का प्रदर्शन
2021 के विधानसभा चुनाव में एआईएनआरसी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं, भाजपा ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीतीं, जबकि एआईएडीएमके को 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली।
पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बार का चुनाव गठबंधन समीकरण, उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दों के आधार पर बेहद दिलचस्प होने वाला है।

ईद के जश्न के बीच बिहार के इस जिले में लगा खामेनेई का पोस्टर, युवाओं में मची सेल्फी लेने की होड़

पटना। देशभर में हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ ईद मनाई गई। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद लोग एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते नजर आए। देश के विभिन्न हिस्सों में उत्सव का माहौल बना रहा। युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। ईद के मौके पर देशभर से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोजपुर जिले के आरा शहर में अलग नजारा देखने को मिला। यहां भाईचारे, आपसी सौहार्द और मोहब्बत के साथ जश्न मनाया गया। इसी दौरान, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनेई के पोस्टर के साथ सेल्फी लेने की होड़ रही। शहर के गोपाली चौक घंटाघर क्षेत्र में ईरान-अमेरिका संघर्ष में मारे गए बताए जा रहे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का पोस्टर लगाया गया। पोस्टर के सामने युवाओं ने सेल्फी ली और एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दीं। वहां से गुजरने वाले लोगों के बीच खामेनेई की तस्वीर चर्चा का विषय बनी रही। अमेरिका व इजराइली हमले में पिछले महीने फरवरी के अंतिम सप्ताह में खामेनेई की मौत हुई थी। वह शिया समुदाय से संबंध रखते थे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पिता की पंरपरा को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को ईद के अवसर पर यहां ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे जहां नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। नीतीश कुमार गांधी मैदान नहीं पहुंचे, जिनके राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने की संभावना है। सुबह की हल्की बारिश के बीच लोगों ने वहां नमाज अदा की। नीतीश ने शहर के कई 'खानकाहों' (सूफी मठों) का दौरा कर समुदाय के नेताओं को ईद की मुबारकबाद दी और त्योहार पर बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया। गांधी मैदान में नमाजियों ने 44 वर्षीय निशांत का गर्मजोशी से स्वागत किया। हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाले निशांत करीब दो हफ्ते पहले अपने पिता की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में शामिल हुए। आमतौर पर कम बोलने वाले निशांत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ''मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बिहार और पूरे देश के लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अल्लाह हम सभी पर अपनी बरकत बनाए रखें।
मध्यप्रदेश में शिया समुदाय के अधिकांश लोगों ने शनिवार को ईद का त्यौहार नहीं मनाया और अमेरिका-इजराइल हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं,सुन्नी समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ राज्यभर में ईदगाहों में नमाज अदा कर त्यौहार मनाया। देशभर में शनिवार को ईद मनाई गयी। शिया समुदाय के लोगों ने ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए।

काबुल में पाकिस्तान ने किया नरसंहार, मदद के लिए भारत ने तुरंत बढ़ाया हाथ, अफगान जनता बोली- शुक्रिया भारत

काबुल। काबुल पर बरसी आग, पाकिस्तान का हमला और भारत की मानवीय मदद, यह केवल एक खबर नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर का खतरनाक संकेत है। सोलह मार्च की रात, जब रमजान का पाक महीना चल रहा था और लोग इबादत में डूबे थे, उसी समय पाकिस्तान की वायु सेना ने काबुल के एक नशा मुक्ति केंद्र पर बम बरसाकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस हमले में चार सौ से अधिक लोग मारे गए और ढाई सौ से ज्यादा घायल हुए। यह कोई साधारण लक्ष्य नहीं था, बल्कि दो हजार बिस्तरों वाला वह केंद्र था जहां समाज के सबसे कमजोर और बेबस लोग इलाज करा रहे थे।
यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह एक सुनियोजित संदेश था कि क्षेत्र में अस्थिरता को और भड़काया जाएगा। पाकिस्तान की यह कार्रवाई उसकी रणनीतिक बेचैनी और आक्रामक नीति का खुला प्रदर्शन है। नागरिकों को निशाना बनाना, वह भी एक चिकित्सा केंद्र में, अंतरराष्ट्रीय मानकों और मानवीय मूल्यों की खुली अवहेलना है।
लेकिन इस भयावह तबाही के बीच भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह केवल ताकत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी नाम है। हमले के चार दिन के भीतर ही भारत ने काबुल के लिए ढाई

टन आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेज दी। इसमें जरूरी दवाइयां, उपचार सामग्री, उपकरण और राहत किट शामिल थे। यह कदम केवल राहत नहीं, बल्कि एक मजबूत कूटनीतिक संदेश भी है।
भारत ने साफ शब्दों में कहा कि वह अफगान जनता के साथ खड़ा है और इस कठिन समय में हर संभव मानवीय सहायता देता रहेगा। यह बयान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत भारत लंबे समय से अफगानिस्तान के स्वास्थ्य और पुनर्निर्माण में सहयोग करता रहा है। खासकर नशे की समस्या से जूझ रहे अफगान समाज के लिए यह सहायता बेहद महत्वपूर्ण है।
रणनीतिक नजरिये से देखें तो यह घटनाक्रम कई स्तरों पर गहरी अहमियत रखता है। एक तो पाकिस्तान का यह हमला क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। इससे यह संकेत मिलता है कि वह अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी सैन्य कार्रवाई करने से नहीं हिचक रहा। साथ ही, इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की छवि को और धूमिल किया है। नागरिकों पर हमला किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता।
इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत की भूमिका है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश के, सीधे मानवीय सहायता पहुंचाकर यह दिखा दिया कि वह क्षेत्र में जिम्मेदार शक्ति है। यह कदम भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है और अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्तों को और गहरा बनाता है।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह हमला ऐसे समय हुआ जब अफगानिस्तान पहले ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में एक नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाना स्थिति को और भयावह बना देता है। बचाव दल कई दिनों तक मलबे से शव निकालते रहे, आग की लपटें और चीखें इस त्रासदी की भयावहता को बयान करती रहीं।
भारत की त्वरित प्रतिक्रिया यह भी दर्शाती है कि वह केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय और संवेदनशील कूटनीति पर काम करता है। यह कदम पाकिस्तान के आक्रामक रवैये के मुकाबले एक नैतिक और रणनीतिक संतुलन स्थापित करता है।

गलवान के बाद भारत-चीन रिश्तों में सुधार के संकेत, एयर चाइना फिर शुरू करेगा दिल्ली-बीजिंग सीधी उड़ान

नई दिल्ली। गलवान घाटी संघर्ष के बाद तनावपूर्ण रहे भारत-चीन संबंधों में अब सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में एयर चाइना ने बीजिंग और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है।
भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने बताया कि यह कदम केवल यात्रा सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
इससे पहले भी दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं की बहाली शुरू हो चुकी है। इंडिगो ने नई दिल्ली और शंघाई के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की है, जबकि एयर इंडिया ने भी शंघाई-दिल्ली मार्ग पर अपनी सेवाएं दोबारा शुरू की हैं। इसके अलावा, चाइना ईस्टर्न एयरलाइन पहले ही शंघाई से दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू कर चुकी है।
गौरतलब है कि वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था, जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों की जान गई थी। इसके बाद से दोनों देशों

के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर लगातार बातचीत होती रही है।
अगस्त 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, जिसमें तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का दौरा भी किया, जिससे रिश्तों में सुधार की दिशा को बल मिला।
विशेषज्ञों का मानना है कि हवाई संपर्क की बहाली और बढ़ती कूटनीतिक बातचीत से भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि सीमा विवाद जैसे मुद्दे अभी भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं।

ईरान का दावा–इजरायली फाइटर जेट को बनाया निशाना, इजरायल ने नुकसान से किया इनकार

तेहरान/तेल अवीव। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने एक इजरायली लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। यह दावा ऐसे समय सामने आया है, जब एक दिन पहले ही अमेरिकी एफ-35 विमान को लेकर भी इसी तरह की खबरें सामने आई थीं।
ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने इजरायली विमान पर हमला किया। वहीं, इजरायल ने इस घटना को स्वीकार करते हुए कहा कि उसके विमान पर ईरानी हवाई क्षेत्र में उड़ान के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई थी।
हालांकि, इजरायल रक्षा बलों के अनुसार, पायलट ने मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मिसाइल के खतरे को टाल दिया और मिशन को बिना किसी नुकसान के पूरा किया। किसी भी तरह की क्षति या हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिसाइल विमान के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण बड़ा नुकसान टल गया। इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया है कि ईरान के हवाई क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां कितनी जोखिम भरी हो चुकी हैं।
नतांज परमाणु संयंत्र पर हमला
इसी बीच, ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया कि नतांज परमाणु संवर्धन संयंत्र पर दो बार हवाई हमला हुआ, हालांकि किसी प्रकार के विकिरण रिसाव की जानकारी नहीं मिली है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की घेराबंदी, यूएस-यूके समेत 22 देशों ने जारी किया कड़ा संयुक्त बयान

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्धविराम में दिलचस्पी नहीं रखता और सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को ईरान से संबंधित हमलों के लिए अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इस बीच, ईरान के नेता मोजतबा खामेनेई ने पड़ोसी देशों में हमलों के लिए इजरायल पर आरोप लगाया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। मध्य पूर्व में संघर्ष प्रमुख देशों के कड़े बयानों और नए घटनाक्रमों के साथ और तीव्र होता जा रहा है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ईरान ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संघर्ष के इस चरण में अमेरिका युद्धविराम की तलाश में नहीं है। व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैन्य अभियान अभी भी मुख्य केंद्र बिंदु हैं। ट्रंप ने कहा कि हालांकि बातचीत संभव है, लेकिन फिलहाल लड़ाई रोकना प्राथमिकता नहीं है।
ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को ईरानी मिसाइल खतरों से संबंधित अभियानों के लिए अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करना है, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्ग है। हालांकि, ट्रंप ने ब्रिटेन के इस फैसले के समय पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए था। इस बीच, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने ओमान और तुर्की में हमले करने के

लिए इजरायल पर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच गलतफहमी और तनाव पैदा करना था। उनके अनुसार, ये कदम क्षेत्र को विभाजित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य पर संयुक्त बयान
संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है, हम खाड़ी में निहत्थे वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया हमलों, तेल और गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों और ईरानी सेना द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को वस्तुतः बंद करने की कड़ी निंदा करते हैं। बयान में आगे कहा गया है हम बढ़ते संघर्ष पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम ईरान से आग्रह करते हैं कि वह अपनी धमकियों, बारूदी सुरंग बिछाने, ड्रोन और मिसाइल हमलों और वाणिज्यिक जहाजों के लिए जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने के अन्य प्रयासों को तुरंत बंद करे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करे।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)